facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 09 मार्च 2026 ● वर्ष 7 ● अंक 34 ● मूल्यः 5 रुपए

रैपर से राजा तक: बालेन की तेज चढ़ाई

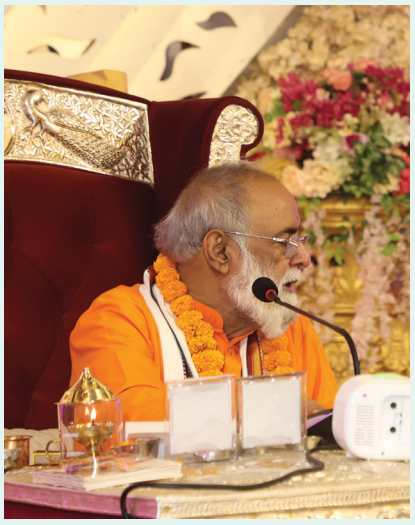

बहुत विनम्र और सहज हैं पूज्य कुमार स्वामी जी

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

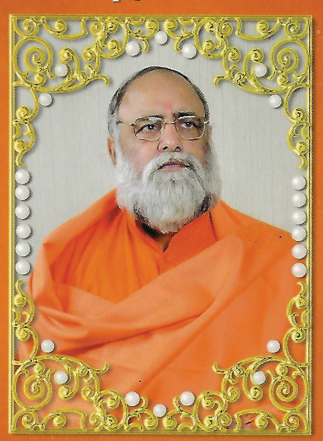

दिव्य पाठ से मस्तिष्क जाग्रत अवस्था में आ जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवाह विद्युत की भांति तरंगित हो उठता है। इसके विवेक को अकल्पनीय ऊर्जा मिलती है।

●

तथाकथित गुरु और संत हमें चिंतन नहीं देते बल्कि भयभीत कर के चिंता दे देते हैं। सच्चा गुरु वही है जो मनुष्य को चिताओं और भय से मुक्त करे।

●

भौतिक संपन्नता के बावजूद पश्चिम जगत के देश दुखी हैं। केवल अध्यात्म और दिव्या पाठ ही सच्चा सुख प्रदान करने में सक्षम हैं।

होली का रंग कैसे बना खून का दाग

उत्तम नगर हत्याकांड में 3 महिलाएं हिरासत में, इलाके में अब भी तनाव

@ भारतश्री ब्यूरो

दिल्ली की होली आमतौर पर रंग, गुलाल और हंसी-मजाक के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार राजधानी के एक इलाके में यही होली एक दर्दनाक कहानी बन गई। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते-देखते हिंसा में बदल गया और 26 वर्षीय युवक तरुण की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके का माहौल बदल गया। जहां एक दिन पहले तक रंग और उत्साह था, वहीं अगले ही दिन गुस्सा, डर और सन्नाटा दिखाई देने लगा।अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद ये महिलाएं दिल्ली के ख्याला इलाके में छुपी हुई थीं।

तीन महिलाओं से पूछताछ

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सायरा, शरीफ और सलमा नाम की तीन महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा गया है ताकि घटना के पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके।जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया था। तीन और महिलाओं के पकड़े जाने के बाद कुल गिरफ्तारी की संख्या दस तक पहुंच गई है।

एक गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार होली के दिन माहौल सामान्य था। बच्चे सड़कों पर रंग खेल रहे थे और कई जगहों पर लोग एक-दूसरे को गुलाल लगा रहे थे।इसी दौरान पानी से भरा एक गुब्बारा पड़ोस की एक महिला पर गिर गया। सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं होली के दिन अक्सर मजाक में खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस बार मामला बिगड़ गया।बताया जाता है कि गुब्बारा गिरने के बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहले

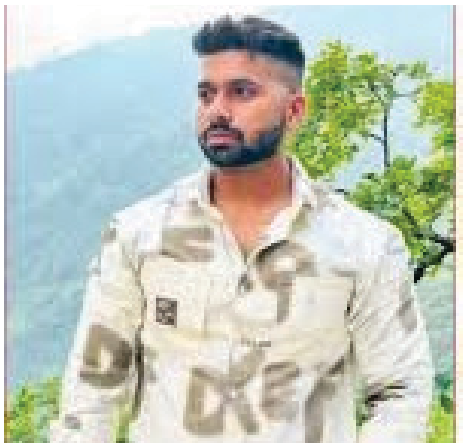

बहस हुई, फिर झगड़ा बढ़ता गया और देखते-देखते कई लोग इसमें शामिल हो गए।कुछ ही देर में यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान 26 वर्षीय तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इलाके में फैला गुस्सा

तरुण की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। 6 मार्च को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए।गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। सड़क पर तनाव का माहौल बन गया और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा।स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी शामिल किए गए।

बुलडोजर कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा

घटना के कुछ दिन बाद नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी उमरदीन के पिता निजामुद्दीन के घर के कुछ हिस्सों को गिरा दिया।नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा थी। उनके अनुसार घर के कुछ हिस्से नालियों पर बने हुए थे, जिन्हें हटाया गया।हालांकि इस कार्रवाई को लेकर इलाके में काफी चर्चा भी हुई। कुछ लोगों ने इसे कानून के तहत कार्रवाई बताया, तो कुछ लोगों ने इसे घटना से जोड़कर देखा।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है।सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की पूरी कड़ी जोड़ी जा रही है।जांच में यह भी देखा जा रहा है कि झड़प के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे और किसकी क्या भूमिका रही।तरुण के परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। परिवार का कहना है कि एक छोटी सी बात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की है।परिजनों का कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

बाजार और कारोबार पर असर

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।इसका असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ा है। कई दुकानों के शटर बंद हैं और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।छोटे दुकानदारों का कहना है कि होली के बाद का समय आमतौर पर अच्छा कारोबार लेकर आता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

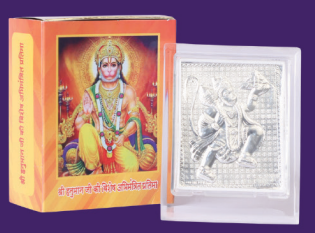

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

भारतीय कंपनी की बड़ी छलांग, 50 साल बाद अमेरिका में बनेगी नई ऑयल रिफाइनरी

भारत की कंपनी का ग्लोबल दम, टेक्सस में 300 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाएगी रिलायंस

@ शोभित यादव

दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यापार नहीं बदलते, बल्कि देशों के रिश्तों और ताकत के समीकरण भी बदल देते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक फैसला सामने आया है। भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका में नई ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश का फैसला किया है।अमेरिका में पिछले लगभग पचास वर्षों में यह पहली नई ऑयल रिफाइनरी होगी। इस प्रोजेक्ट की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 11 मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की। ट्रम्प ने इस समझौते को ऐतिहासिक डील बताते हुए कहा कि यह करीब 300 अरब डॉलर यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपये का निवेश है। उनके शब्दों में यह अमेरिकी वर्कर्स, ऊर्जा क्षेत्र और टेक्सस के लोगों के लिए बड़ी जीत है।लेकिन इस खबर के पीछे केवल एक निवेश की कहानी नहीं है। यह उस सफर की कहानी भी है, जिसमें एक भारतीय कंपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ऊर्जा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है।

टेक्सस में बनेगी नई रिफाइनरी

यह विशाल रिफाइनरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित पोर्ट ऑफ ब्राउनस्विले में बनाई जाएगी। यह इलाका टेक्सस राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और समुद्री व्यापार केंद्र माना जाता है।रिफाइनरी बनने के बाद यहां कच्चे तेल को प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन तैयार किए जाएंगे। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका के घरेलू बाजारों में इस्तेमाल होगा।ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि यह दुनिया की सबसे साफ और आधुनिक रिफाइनरी होगी। उनका दावा है कि इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जिससे पर्यावरण पर असर कम से कम पड़े।

क्यों खास है यह फैसला

अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां पिछले लगभग पांच दशकों से कोई नई बड़ी रिफाइनरी नहीं बनी।इसका मुख्य कारण सख्त पर्यावरण नियम, भारी निवेश लागत और पुरानी रिफाइनरियों का विस्तार रहा है। कंपनियां नई रिफाइनरी लगाने के बजाय पुराने प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने को ज्यादा सुरक्षित मानती थीं।ऐसे माहौल में किसी विदेशी कंपनी का अमेरिका में जाकर नई रिफाइनरी लगाना अपने आप में बड़ा कदम माना जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को भी दर्शाता है।

जामनगर का अनुभव बनेगा ताकत

रिलायंस के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक है। कंपनी गुजरात के जामनगर में विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स चलाती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी हब माना जाता है।जामनगर की रिफाइनरी केवल आकार में बड़ी नहीं है, बल्कि तकनीक और दक्षता के मामले में भी दुनिया के अग्रणी प्लांट्स में गिनी जाती है।इसी अनुभव और तकनीक को अब टेक्सस के नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा।ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जामनगर मॉडल ने रिलायंस को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

हजारों नौकरियों की उम्मीद

इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा असर रोजगार के क्षेत्र में भी दिखाई देगा।नई रिफाइनरी के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। निर्माण के दौरान इंजीनियर, तकनीशियन और श्रमिकों की बड़ी संख्या की जरूरत होगी।इसके अलावा रिफाइनरी शुरू होने के बाद भी लंबे समय तक स्थायी रोजगार के अवसर बनेंगे।ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि यह निवेश अमेरिकी कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा सवाल

आज के दौर में ऊर्जा केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हिस्सा बन चुकी है।किसी देश के पास पर्याप्त ईंधन और ऊर्जा संसाधन होना उसकी रणनीतिक ताकत को बढ़ाता है।ट्रम्प ने कहा कि यह रिफाइनरी अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी।उनका दावा है कि इससे अमेरिका फिर से "एनर्जी डॉमिनेंस" यानी ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक दबदबा हासिल कर सकेगा।

भारत के लिए क्या मायने

भारत के लिए यह निवेश केवल व्यापारिक उपलब्धि नहीं है।यह उस बदलाव का संकेत है जिसमें भारतीय कंपनियां अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।आज भारतीय कंपनियां तकनीक, पूंजी और प्रबंधन क्षमता के दम पर दुनिया के बड़े बाजारों में निवेश कर रही हैं।रिलायंस का यह कदम उसी बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है।

एक भारतीय कंपनी की वैश्विक पहचान

रिलायंस आज भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी केवल तेल और गैस क्षेत्र तक सीमित नहीं है।यह हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विस, रिटेल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है।पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने तकनीक और ऊर्जा के नए क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार किया है।टेक्सस में बनने वाली नई रिफाइनरी इसी विस्तार की एक बड़ी कड़ी मानी जा रही है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलता दौर

दुनिया में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी तेल और गैस वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का बड़ा हिस्सा हैं।इसी वजह से आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल रिफाइनरियों की जरूरत बनी हुई है।टेक्सस में बनने वाला यह प्रोजेक्ट इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक प्रतीकात्मक कहानी

अगर इस खबर को केवल आंकड़ों में देखा जाए तो यह 300 अरब डॉलर का निवेश है। लेकिन अगर इसे एक कहानी की तरह देखा जाए, तो यह उस यात्रा की कहानी है जिसमें एक भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जाकर ऊर्जा का नया अध्याय लिखने जा रही है।कभी भारत ऊर्जा तकनीक के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर था। आज वही भारत अपनी कंपनियों के जरिए वैश्विक ऊर्जा ढांचे को आकार देने की स्थिति में पहुंच रहा है।

जामनगर की रिफाइनरी से शुरू हुआ सफर अब टेक्सस के तट तक पहुंच गया है।और शायद यही इस खबर का सबसे बड़ा संदेश है-भारत की कंपनियां अब केवल बाजार का हिस्सा नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक कहानी की प्रमुख पात्र बन चुकी हैं।

चीन का नया कानून, क्या खत्म होगी सांस्कृतिक विविधता?

56 जातियां, एक पहचान, चीन के नए कानून पर दुनिया की नजर

@ मनीष पांडेय

बीजिंग की ठंडी सुबह है। संसद भवन के विशाल गलियारों में नेताओं की आवाजाही तेज हो गई है। चीन की सत्ता के केंद्र में एक ऐसा कानून आकार ले रहा है, जो आने वाले समय में देश की सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यह कानून है -Law on Promoting Ethnic Unity and Progress।सरकार का दावा है कि यह कानून चीन की 56 जातीय समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान देगा। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को डर है कि यह कदम चीन की सांस्कृतिक विविधता को सीमित कर सकता है।यह कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है। यह कहानी है पहचान, संस्कृति, सत्ता और राष्ट्रवाद की-और उस रास्ते की, जिस पर चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping देश को ले जाना चाहते हैं।

56 जातियां, एक राष्ट्र की कहानी

चीन दुनिया के सबसे विविध समाजों में से एक है। यहां हान, उइगर, तिब्बती, मंगोल, झुआंग, हुई जैसे कुल 56 आधिकारिक जातीय समूह रहते हैं।इनमें सबसे बड़ा समुदाय हान है, जो चीन की आबादी का लगभग 90 प्रतिशत है। बाकी समुदायों को एथनिक माइनॉरिटी कहा जाता है।इन अल्पसंख्यक समुदायों की अपनी-अपनी भाषाएं, परंपराएं, खान-पान और धार्मिक मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए-उइगर समुदाय तुर्किक मूल का मुस्लिम समुदाय है।तिब्बती लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। मंगोल समुदाय की अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक परंपरा है। इतनी विविधता के बीच चीन हमेशा से राष्ट्रीय एकता को लेकर बेहद सतर्क रहा है।यही कारण है कि चीन की सत्ता लंबे समय से यह कोशिश करती रही है कि अलग-अलग समुदायों के बीच कोई ऐसी पहचान न बने जो राष्ट्रीय पहचान से बड़ी हो जाए।

नया कानून क्या कहता है?

प्रस्तावित कानून के कई ऐसे प्रावधान हैं जो चीन की सामाजिक व्यवस्था को सीधे प्रभावित करेंगे।सबसे पहला बदलाव भाषा को लेकर है।सरकार चाहती है कि पूरे देश में मंदारिन भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाए। इसका मतलब यह हो सकता है कि स्थानीय भाषाओं का महत्व धीरे-धीरे कम हो जाए।

दूसरा बड़ा कदम अंतर-जातीय विवाह को लेकर है

सरकार अलग-अलग जातीय समुदायों के बीच शादी को प्रोत्साहित करना चाहती है। अगर कोई ऐसी शादी को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे गलत माना जाएगा।तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद प्रावधान बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है।इस कानून के अनुसार माता-पिता को अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे चीन और कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम करें।यह प्रावधान सीधे तौर पर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी Chinese Communist Party की वैचारिक पकड़ को मजबूत करता है।कानून में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे अलग-अलग जातीय समुदायों के बीच नफरत या अलगाव की भावना पैदा हो।सरकार का कहना है कि यह सब राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता के लिए जरूरी है।

क्यों चिंतित है चीनी सरकार?

राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले कुछ वर्षों से एक विचार को बार-बार दोहराते रहे हैं-धर्म और संस्कृति का चीनीकरण।इसका मतलब यह है कि चीन में मौजूद सभी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं देश की आधिकारिक विचारधारा और राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप हों।विशेषज्ञ मानते हैं कि नया कानून इसी नीति को कानूनी रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।अमेरिका की University of Pennsylvania से जुड़े विशेषज्ञ एरन ग्लासरमैन का कहना है कि सरकार पहले से ही कई क्षेत्रों में ऐसी नीतियां लागू कर रही थी। अब उन्हें औपचारिक कानून बनाया जा रहा है।चीन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सरकार की चिंता ज्यादा रहती है।इनमें सबसे प्रमुख हैं-Xinjiang, Tibet। शिनजियांग में उइगर मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। वहीं तिब्बत में लंबे समय से चीन के शासन के खिलाफ विरोध होता रहा है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले Lhasa में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे।कुछ साल बाद Urumqi में उइगर और हान समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई।इन घटनाओं के बाद चीन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया।

री-एजुकेशन कैंप का विवाद

मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने शिनजियांग में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को हिरासत शिविरों में रखा।संयुक्त राष्ट्र सहित कई संस्थाओं ने इन शिविरों को लेकर चिंता जताई है।लेकिन चीन सरकार इन जगहों को री-एजुकेशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बताती है।सरकार का कहना है कि इन केंद्रों का उद्देश्य लोगों को कट्टरपंथ से दूर करना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है।रिपोर्टों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में धार्मिक गतिविधियों पर भी सीमाएं लगाई गई हैं और कई मस्जिदें बंद कर दी गईं।

स्थानीय भाषाएं और परंपराएं होंगी धीरे-धीरे कमजोर

चीन सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय एकता के बिना विकास संभव नहीं है।सरकारी प्रवक्ता Lou Qinjian का कहना है कि नया कानून अलग-अलग समुदायों को देश के विकास से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद करेगा।सरकार का यह भी कहना है कि कई अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं, इसलिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है।इस दृष्टिकोण में हान संस्कृति को अक्सर आधुनिक और प्रगतिशील माना जाता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कानून न्यायिक व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि एक वैचारिक ढांचा तय करने के लिए बनाया जा रहा है।इसके जरिए शिक्षा, मीडिया, इंटरनेट, पर्यटन, धर्म और इतिहास-सभी क्षेत्रों में एक साझा चीनी पहचान को बढ़ावा दिया जाएगा।आलोचकों को डर है कि इससे स्थानीय भाषाएं और परंपराएं धीरे-धीरे कमजोर हो सकती हैं।एक सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही हैआज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी वैश्विक ताकत लगातार बढ़ रही है।लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है-क्या एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए सांस्कृतिक विविधता को सीमित करना जरूरी है?या फिर विविधता ही किसी समाज की असली ताकत होती है?विश्लेषकों का मानना है कि चीन को अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस कानून की जरूरत नहीं है।लेकिन यह कानून एक संकेत जरूर देता है।यह संकेत है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले वर्षों में चीन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं-एक ऐसा देश जहां राष्ट्रीय पहचान सबसे ऊपर हो।और शायद यही इस कानून की असली कहानी है।यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश है।

तिब्बत में बदलती शिक्षा व्यवस्था

तिब्बत में भी शिक्षा और धर्म से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं।अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मंदारिन भाषा में पढ़ाई करनी होती है।उन्हें पारंपरिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है।पहले तिब्बत में बच्चे मठों में जाकर भिक्षु बनने की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब उस व्यवस्था पर भी नियंत्रण बढ़ गया है। हाल के वर्षों में इनर मंगोलिया में मंगोलियन भाषा की पढ़ाई को लेकर विरोध हुआ।वहीं निंग्शिया क्षेत्र में कुछ मस्जिदों को गिराने के आदेश पर भी विवाद सामने आया।इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या चीन की नीतियां वास्तव में विविधता को स्वीकार करती हैं, या धीरे-धीरे एक ही सांस्कृतिक ढांचे की ओर बढ़ रही हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर

नीतीश कुमार का CM पद से विदाई का ऐलान

बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। 5 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इससे साफ हो गया कि वे अब विधानसभा की राजनीति से दूर हो रहे हैं और दिल्ली की संसदीय दुनिया में कदम रखेंगे। नीतीश कुमार, जो बिहार की सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, ने कई बार गठबंधन बदले हैं, लेकिन इस बार उनका फैसला कुछ अलग लग रहा है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत कहा कि अब बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री बनेगा। यह खबर आते ही पटना की सड़कों पर बहस छिड़ गई। विपक्षी दल इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, जबकि एनडीए के समर्थक इसे प्राकृतिक बदलाव कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल करते समय कहा कि वे थक चुके हैं और नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ उनकी इच्छा है या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा? बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45। गठबंधन में दोनों मिलकर 123 का आंकड़ा पार करते हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। अब नीतीश के जाने के बाद बीजेपी के पास विकल्प खुल गए हैं। पार्टी के अंदर नाम चर्चा में हैं जैसे सम्राट चौधरी या निशिकांत दुबे। यह बदलाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। विपक्ष कहता है कि यह जनादेश का अपमान है, क्योंकि 2020 में नीतीश ही सीएम चुने गए थे। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि गठबंधन में सब कुछ साझा होता है। यह घटना बिहार के लोगों के लिए नया दौर ला रही है, जहां विकास और जाति की राजनीति का मिश्रण और तेज होगा। कुल मिलाकर, यह कदम बिहार की सत्ता संरचना को हमेशा के लिए बदल सकता है, और जनता अब देख रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

नीतीश का राज्यसभा रुख: थकान या मजबूरी का खेल?

नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना कोई अचानक फैसला नहीं लगता। वे 75 साल के हो चुके हैं और बिहार की कुर्सी पर 20 से ज्यादा साल बिताए हैं। नामांकन के समय उन्होंने कहा कि वे अब आराम चाहते हैं और पार्टी को मजबूत नेतृत्व देना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बीजेपी के दबाव का नतीजा है। 2022 में जब नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिलाया था, तब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का लालच दिया था, लेकिन नीतीश ने मना कर दिया। अब, एनडीए में वापसी के बाद, यह प्रस्ताव फिर आया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में नीतीश से लंबी बैठक की, जिसके बाद यह फैसला हुआ। राज्यसभा में जेडीयू को दो सीटें मिल रही हैं, एक नीतीश को और दूसरी किसी युवा नेता को। इससे जेडीयू की संसदीय ताकत बढ़ेगी, लेकिन बिहार में उनका सीएम पद चला जाएगा। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे 'पीडीए का अपमान' कहा है, जहां पीडीए का मतलब पसमांदा, दलित, पिछड़ा है। वे कहते हैं कि नीतीश को पीएम बनाना था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें किनारे कर दिया। दूसरी तरफ, बीजेपी कहती है कि यह नीतीश की मर्जी है और वे उन्हें सम्मान दे रहे हैं। राज्यसभा जाकर नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय रह सकेंगे, जहां वे विकास के मुद्दों पर मोदी सरकार का साथ देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मजबूरी है? बिहार में जेडीयू की ग्राउंड ताकत कम हो रही है, और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। नीतीश का जाना जेडीयू को कमजोर कर सकता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मंच मिलेगा। यह फैसला बिहार की स्थानीय राजनीति को बीजेपी के हवाले कर देगा, जहां जातिगत समीकरण बदलने की कोशिशें तेज होंगी। कुल मिलाकर, नीतीश का यह कदम व्यक्तिगत थकान और राजनीतिक समायोजन का मिश्रण लगता है, जो आने वाले दिनों में साफ होगा।

6 राज्यों में BJP की चालाकी: सहयोगी को हटाकर खुद सत्ता की कमान

बीजेपी की राजनीति में एक पैटर्न साफ दिखता है, जहां वे सहयोगी दलों को साथ लेकर सत्ता में आते हैं, लेकिन बाद में अपना मुख्यमंत्री बनवा लेते हैं। बिहार इसका सातवां उदाहरण बन सकता है। पहले कर्नाटक की बात करें। 2019 में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन गिराने के लिए बीजेपी ने 'ऑपरेशन लोटस' चलाया। 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आने से कमलनाथ सरकार गिरी, और शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बने। महाराष्ट्र में 2022 का मामला याद करें, जहां शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे को हटाया गया। शिंदे सीएम बने, लेकिन बीजेपी ने वादा किया कि जल्द उनका नेता आएगा। गोवा में 2019 में कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई, और प्रमोद सावंत सीएम बने। हरियाणा में 2024 में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, ताकि जाट वोटों को संभाला जाए। उत्तराखंड में 2021 में तीरथ सिंह रावत को धीरेंद्र तोमर की जगह लाया गया, जो बीजेपी का अपना चेहरा था। इन 6 राज्यों में पैटर्न एक जैसा है: पहले गठबंधन, फिर विधायकों को तोड़ना या दबाव बनाना, और आखिर में अपना नेता सीएम। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह रणनीति बीजेपी को स्थानीय चेहरा देती है और चुनाव में मजबूत बनाती है। लेकिन आलोचक इसे लोकतंत्र का मजाक बताते हैं, क्योंकि जनादेश का सम्मान नहीं होता। बिहार में भी यही हो रहा है। नीतीश को राज्यसभा भेजकर बीजेपी बिना गठबंधन तोड़े सत्ता ले रही है। यह चाल बीजेपी की केंद्रीय कमान की सोच है, जो अमित शाह की अगुवाई में चलती है। इन उदाहरणों से साफ है कि सहयोगी दलों को इस्तेमाल कर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाती है। लेकिन क्या यह लंबे समय तक चलेगा? जनता का विश्वास कम हो सकता है। कुल मिलाकर, ये 6 राज्य बीजेपी की रणनीति का आईना हैं, जो बिहार को भी दिखा रहे हैं।

बिहार पर BJP राज का असर: विकास बनेगा या जाति का चक्कर?

नीतीश कुमार के जाने से बिहार में बीजेपी का सीएम बनना कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले तो विकास का मुद्दा। नीतीश के समय बिहार में सड़कें, स्कूल और बिजली का काम तेज हुआ। बीजेपी कहती है कि वे इसे और आगे ले जाएंगे, जैसे केंद्र की योजनाओं से जोड़कर। लेकिन विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि बीजेपी का फोकस आरएसएस की विचारधारा पर होगा, जो स्थानीय मुद्दों से दूर है। दूसरा, जाति का खेल। बिहार में ईबीसी और ओबीसी वोट निर्णायक हैं। नीतीश ने पसमांड़ा कार्ड खेला, लेकिन बीजेपी ऊंची जातियों पर निर्भर है। नया सीएम अगर ऊपरी जाति का होगा, तो निचली जातियां नाराज हो सकती हैं। 2025 चुनाव में यह बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। आर्थिक रूप से बिहार गरीब राज्य है, और बीजेपी का वादा निवेश लाने का है। लेकिन जानकार कहते हैं कि बिना स्थानीय चेहरे के मुश्किल होगी। जेडीयू के बिना बीजेपी को विधानसभा में बहुमत जुटाना पड़ेगा, जो जोखिम भरा है। विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह साजिश है, जो बिहार को गुजरात मॉडल की ओर ले जाएगी। गुजरात में विकास तो हुआ, लेकिन असमानता भी बढ़ी। बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं, और बीजेपी को यह साबित करना होगा। ग्रामीण इलाकों में नीतीश की छवि मजबूत थी, अब बीजेपी को नया विश्वास बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह बदलाव बिहार को नई दिशा दे सकता है, लेकिन अगर गलत नेता चुना गया, तो अस्थिरता बढ़ेगी। जनता अब देख रही है कि वादे कितने पूरे होते हैं।

विपक्ष की आवाज बुलंद: साजिश या सियासी हकीकत?

नीतीश के राज्यसभा जाने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे 'जी2 की साजिश' कहा, जहां जी2 से मतलब मोदी-शाह है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि यह पीडीए का अपमान है, और नीतीश को पीएम बनाना था। आरजेडी और अन्य इंडिया गठबंधन के नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बीजेपी जनादेश को तोड़-मरोड़ रही है। दूसरी तरफ, बीजेपी इसे सामान्य बदलाव बताती है, जो गठबंधन की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह साजिश है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हां, क्योंकि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ी थी, अब राज्य स्तर पर मजबूत हो रही है। बिहार जैसे बड़े राज्य पर कब्जा उनके लिए रणनीतिक है। विपक्ष अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंतरिक कलह से परेशान है। अगर वे मजबूत मोर्चा बनाएं, तो 2025 में बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल, बीजेपी ऊपरी हाथ में है। यह घटना पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, जहां गठबंधन टूटने का डर हमेशा रहता है। कुल मिलाकर, विपक्ष की चेतावनी सही लगती है, लेकिन बिना एक्शन के बेकार। जनता का फैसला अंतिम होगा।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 09 मार्च 2026 , विक्रम संवत 2080

ईरान–इज़राइल टकराव के बीच समझौते की आहट

अब ईरान इजरायल युद्ध में कुछ संभावनाएं दिखनी शुरू हो गई हैं। लगता है कि निकट भविष्य में ईरान समझौता कर लेगा क्योंकि रूस और चीन इस युद्ध से बचना चाहते हैं। ईरान के अंदर भी कट्टरपंथी खामनेई के मरने के बाद नेतृत्व अनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति शांति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं दूसरी ओर खामनेई की बनाई गई सेना कट्टरवाद की दिशा में जाना चाहतु है। सेना चाहती है कि हम या तो मरेंगे या मारेंगे लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्रपति चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में युद्ध अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन एक बात और गंभीर है की युद्ध में अमेरिका और इजरायल के जीत जाने के बाद क्या होगा। अब तक का इतिहास बताता है की तानाशाही में आंतरिक शांति होती है किंतु तानाशाह सारी दुनिया को अशांत बनाए रखता है दूसरी ओर लोकतंत्र में आंतरिक अशांति होती है और दुनिया खतरे से बची रहती है। स्पष्ट है कि ईरान में भी जब लोकतंत्र आ जाएगा इसराइल और अमेरिका जीत जाएंगे तो आंतरिक व्यवस्था में कुछ अराजकता का वातावरण बढ़ेगा यद्यपि दुनिया को इससे शांति मिलेगी। इसलिए मैं लोकतंत्र के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करता हूं भले ही इसके परिणाम स्वरूप इरान में आंशिक रूप से आंतरिक अशांति का वातावरण बढ़े।

बजरंग मुनि

क्या चुनावी लड़ाई INDIA गठबंधन पर भारी पड़ रही है

@ अनुराग पाठक

भारतीय राजनीति में गठबंधन अब केवल गणित का खेल नहीं रह गया है, यह विश्वास और संयम की भी परीक्षा बन चुका है। विपक्षी दलों का साझा मंच बना INDIA गठबंधन इसी भरोसे पर खड़ा किया गया था कि विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद दल एक बड़े राजनीतिक लक्ष्य के लिए साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे-जैसे राज्यों में चुनाव करीब आते हैं, यह भरोसा बार-बार कसौटी पर खड़ा दिखाई देता है। केरल की सियासत में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने इसी सवाल को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है।

केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। एक ओर वामपंथी दलों के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन है, जिसने पिछले दो कार्यकाल से सत्ता संभाल रखी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, जो इस बार सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। स्वाभाविक है कि चुनावी मैदान में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले करेंगे। लेकिन जब यही टकराव उस बड़े मंच तक पहुंच जाए, जहां दोनों दल एक साथ खड़े होने का दावा करते हैं, तब स्थिति जटिल हो जाती है।दरअसल हाल ही में दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें संसद के आगामी सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी थी। यह बैठक सामान्य राजनीतिक विचार-विमर्श का मंच बन सकती थी, लेकिन वहां केरल की राजनीति का विवाद भी पहुंच गया। वामपंथी सांसदों ने आपत्ति जताई कि राहुल गांधी के हालिया बयान गठबंधन की भावना के अनुरूप नहीं हैं।

वामपंथी नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने केरल में जिस तरह से कम्युनिस्ट दलों पर हमला बोला है, वह केवल चुनावी बयानबाजी नहीं है, बल्कि इससे सहयोगी दलों के बीच अविश्वास का माहौल बन सकता है। खासतौर पर उस बयान को लेकर नाराजगी जताई गई जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट दलों और भाजपा के बीच कथित तालमेल की बात कही थी। इससे भी आगे बढ़कर राहुल गांधी ने "कम्युनिस्ट जनता पार्टी" जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने वामपंथी नेताओं को और ज्यादा असहज कर दिया।

राजनीति में शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे संकेत होते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कोई नेता अपने प्रतिद्वंद्वी को किस नजर से देखता है। यही कारण है कि वामपंथी नेताओं ने बैठक में साफ कहा कि अगर सहयोगी दल एक-दूसरे पर ऐसे आरोप लगाने लगेंगे तो गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े होंगे।कांग्रेस की ओर से इस पर अलग रुख सामने आया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा की जाएगी और राहुल गांधी के बयान को उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें वह दिया गया था। उनका कहना था कि संसद सत्र को लेकर हो रही बैठक में किसी भाषण के एक हिस्से को बड़ा मुद्दा बनाना उचित नहीं है। खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि इस पर बाद में विस्तार से बात की जा सकती है और फिलहाल बैठक का ध्यान संसद के एजेंडे पर होना चाहिए।

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति की उस जटिलता को उजागर करता है जिसमें एक ही समय में दो अलग-अलग स्तरों पर राजनीति चलती है। एक स्तर पर राष्ट्रीय राजनीति है, जहां विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य की राजनीति है, जहां वही दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं।केरल इस द्वंद्व का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यहां भाजपा अब भी तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती है, जबकि असली मुकाबला कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन के बीच होता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए वामपंथी सरकार की आलोचना करना राजनीतिक मजबूरी भी है और रणनीति भी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसके लिए चुनावी मैदान में अपनी जगह बनाना कठिन हो जाएगा।

लेकिन यही रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए चुनौती बन जाती है। क्योंकि जब एक सहयोगी दल दूसरे सहयोगी दल को ही भाजपा के करीब बताने लगे, तो यह स्वाभाविक है कि असहजता पैदा होगी। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप आम बात हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति में शब्दों का चयन और भी ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है।

यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या INDIA गठबंधन ने इस तरह की परिस्थितियों के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक मर्यादा तय की है। अगर राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनकी आलोचना की कोई सीमा होगी। या फिर हर दल अपने चुनावी हित के हिसाब से बयान देगा और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात अलग से चलेगी। दरअसल भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह विरोधाभास नया नहीं है। अतीत में भी कई गठबंधन इसी दुविधा से गुजरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर साथ और राज्यों में मुकाबला।

जुबानी तीर

"ईरान लंबे समय से इज़राइल की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं है, लेकिन हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं कर सकते। यदि हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जाती है, तो इज़राइल अपनी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी उम्मीद करते हैं कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखे।

बेंजामिन नेतन्याहू (इज़राइल के प्रधानमंत्री)

"ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या धमकी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हमारा देश अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। हम हमेशा कूटनीतिक समाधान का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन यदि हम पर हमला होता है तो ईरान अपनी रक्षा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा।

अब्बास अराघची (ईरान के विदेश मंत्री)

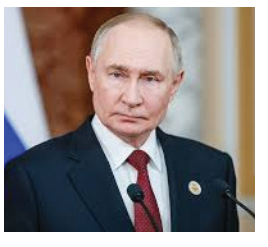

"ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव पूरे मध्य-पूर्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर यह संघर्ष और आगे बढ़ता है तो इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष संयम बरतें और समस्या के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाएं।

व्लादिमीर पुतिन (रूस के राष्ट्रपति)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

विटामिन-E की कमी

छोटी सी लापरवाही से बढ़ सकती हैं कई समस्याएं, आयुर्वेद बताता है प्राकृतिक समाधान

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में लोग फिट और स्वस्थ रहने के लिए तरह-तरह के सप्लीमेंट लेने लगे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व केवल गोलियों से नहीं, बल्कि संतुलित आहार और सही जीवनशैली से मिलते हैं।

इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में एक है विटामिन-E।विटामिन-E शरीर के लिए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह त्वचा, आंखों, मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो धीरे-धीरे कई तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं।

आयुर्वेद के अनुसार शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी केवल भोजन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि पाचन शक्ति, जीवनशैली और मानसिक संतुलन से भी उसका गहरा संबंध होता है। इसलिए विटामिन-E की कमी को समझना और उसका प्राकृतिक उपचार अपनाना बेहद जरूरी है।

विटामिन-E क्यों जरूरी है

विटामिन-E शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने का काम करता है। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है।यह शरीर में बनने वाले फ्री-रैडिकल्स से कोशिकाओं की रक्षा करता है। फ्री-रैडिकल्स ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो उम्र बढ़ने, प्रदूषण और तनाव के कारण शरीर में बनते हैं।विटामिन-E त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह बालों को मजबूत करता है और आंखों की रोशनी के लिए भी लाभकारी माना जाता है।प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

विटामिन-E की कमी से होने वाली बीमारियां

जब शरीर में लंबे समय तक विटामिन-E की कमी बनी रहती है, तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

1. त्वचा संबंधी समस्याएं

विटामिन-E की कमी का सबसे पहला असर त्वचा पर दिखाई देता है। त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। कई लोगों में त्वचा पर झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं।

2. बालों का झड़ना

यदि शरीर में विटामिन-E पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। बालों की चमक भी कम हो जाती है।

3. मांसपेशियों की कमजोरी

विटामिन-E की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। कई लोगों को जल्दी थकान महसूस होती है।

4. आंखों की समस्याएं

आंखों की रोशनी पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में दृष्टि कमजोर होने की शिकायत भी सामने आती है।

5. प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना

यदि शरीर में विटामिन-E कम है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। ऐसे लोगों को बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण हो सकता है।

किन लोगों में ज्यादा होती है इसकी कमी

कुछ लोगों में विटामिन-E की कमी होने की संभावना ज्यादा होती है।

जिन लोगों का भोजन असंतुलित होता है या जो तली-भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, उनमें इसकी कमी देखी जा सकती है।

इसके अलावा जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, उनके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता।

अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और प्रदूषण भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकते हैं।

आयुर्वेद की नजर में समस्या

आयुर्वेद शरीर को केवल अंगों का समूह नहीं मानता, बल्कि इसे दोष, धातु और अग्नि के संतुलन के रूप में देखता है।जब पाचन अग्नि कमजोर होती है, तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व शरीर में ठीक से नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि कई बार लोग अच्छा भोजन करने के बावजूद पोषण की कमी से जूझते हैं।आयुर्वेद के अनुसार विटामिन-E से जुड़ी समस्याएं अक्सर वात और पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ी होती हैं।

आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपाय

आयुर्वेद में प्राकृतिक आहार और जड़ी-बूटियों के माध्यम से शरीर को संतुलित करने पर जोर दिया जाता है।

1. बादाम का सेवन

बादाम विटामिन-E का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। रोज सुबह भीगे हुए 4-5 बादाम खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है।

2. तिल का उपयोग

तिल के बीज भी विटामिन-E से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में तिल को ऊर्जा और पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत बताया गया है।

3. आंवला

आंवला शरीर के लिए अमृत के समान माना जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और त्वचा व बालों के लिए भी बेहद लाभकारी है।

4. नारियल तेल की मालिश

त्वचा और बालों के लिए नारियल तेल से नियमित मालिश करने से भी काफी लाभ मिलता है।

5. घी का सेवन

आयुर्वेद में शुद्ध घी को शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। सीमित मात्रा में घी का सेवन शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है।

जीवनशैली में बदलाव भी जरूरी

केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि जीवनशैली से भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।नियमित व्यायाम और योग करने से शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होती है।पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। नींद की कमी से शरीर की मरम्मत प्रक्रिया प्रभावित होती है।तनाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी बेहद लाभकारी माना जाता है।

प्राकृतिक भोजन सबसे बड़ा उपाय

आजकल लोग पोषण की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत सप्लीमेंट्स की ओर भागते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक भोजन से मिलने वाला पोषण सबसे सुरक्षित और प्रभावी होता है।हरी सब्जियां, मेवे, बीज और फल विटामिन-E के अच्छे स्रोत हैं। यदि इन्हें नियमित आहार में शामिल किया जाए, तो शरीर को आवश्यक पोषण आसानी से मिल सकता है।

स्वस्थ जीवन के लिए केवल बीमारी का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर को संतुलित रखना भी जरूरी है।विटामिन-E की कमी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन यदि समय रहते संतुलित आहार, आयुर्वेदिक उपाय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाई जाए, तो इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है।आयुर्वेद का मूल संदेश भी यही है कि प्रकृति के करीब रहकर ही शरीर को सच्चा स्वास्थ्य मिलता है। जब भोजन प्राकृतिक होगा, जीवनशैली संतुलित होगी और मन शांत रहेगा, तभी शरीर भी स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा।

महात्मा व्यासदास जी का जीवन-चरित्र प्रारम्भिक जीवन और जन्म

महात्मा व्यासदास जी परम रसज्ञ संत थे। उन्होंने हितहरिवंश जी द्वारा बताये गये निकुंज लीला से जुड़े वृन्दावन रस की गहरी और सरस अनुभूति प्राप्त की। मध्यकाल में जब वृन्दावन रस अपने चरम पर था, तब उनकी सरस कृष्ण भक्ति से सारे लोक का कल्याण हुआ। वे पूर्ण निस्पृह, अत्यंत उच्च स्तर के विरागी और कवि हृदय वाले संत थे। वृन्दावन को उन्होंने अपना सबसे बड़ा धन माना। वे चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य के समकालीन थे। हितहरिवंश जी को अपना मार्गदर्शक बनाया। उनकी वाणी की कृपा से वृन्दावन का रसराजत्व जागा, माधुर्य रस का यौवन उमड़ पड़ा। वे वैराग्य के जीवंत रूप थे।

उन्होंने कहा कि वृन्दावन ही असली घन है। करोड़ों सोने के पहाड़ छोड़कर नन्दनन्दन का भजन करना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। वृन्दावन में राधारानी की चरण धूलि की लक्ष्मी भी बलिहारी लेती है। गोपियों का नित्य रास चलता रहता है और कृष्ण वंशी बजाते रहते हैं। वृन्दावन की लीला अद्भुत है, उसका वैभव भी अद्भुत है। व्यास जी ने वृन्दावन के इस रस वैभव को प्रकट किया। उनका पूरा जीवन भगवान की लीला भक्ति के प्रकट होने का प्रतीक था।

उस समय दिल्ली की सत्ता लोदी और सूर वंश से निकलकर मुगलों के हाथ जा रही थी। देश बाबर के आक्रमण से डरा हुआ था। केन्द्रीय शासन कमजोर हो रहा था। प्रांतों के शासक अलग होने की कोशिश में लगे थे। ऐसे समय में मध्य भारत के ओरछा राज्य को महात्मा व्यास ने जन्म लेकर गौरवान्वित किया। ओरछा में महाराज मधुकर शाह राज कर रहे थे। परम पवित्र वेत्रवती नदी के किनारे सम्वत 1567 में मार्गशीर्ष पंचमी को ओरछा में उनका जन्म हुआ। नाम हरिराम रखा गया।

पिता सुमोखन शुक्ल पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा बराबर थी। माता पद्मावती बहुत शीलवती और सुशिक्षित थीं। माता-पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी व्यवस्था की। सुमोखन शुक्ल ने खुद युगल मंत्र की दीक्षा देकर भक्ति का प्रकाश दिखाया। हरिराम बड़े ज्ञानी और शास्त्रों में पारंगत थे। यौवन में सुशीला नाम की कन्या से विवाह हुआ। लेकिन गृहस्थ जीवन में उनकी रुचि नहीं थी। वे शास्त्रार्थ और पढ़ाई में ही समय बिताते थे। उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर महाराज मधुकर शाह ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था।

विद्वत्ता और वैराग्य की ओर

पिता के स्वर्गवास के बाद वे ओरछा के राजगुरु बने। वे पंडितों को ढूंढकर शास्त्रार्थ करने जाते और जीतने में बड़ा आनन्द मिलता। एक बार काशी गए। काशी के बड़े-बड़े शास्त्री उनकी विद्वत्ता मान गए। उन्हें 'व्यास' की उपाधि दी गई। श्रावण मास में विश्वनाथ जी का अभिषेक किया और विशेष कृपा पाई। काशी में रहते एक साधु ने स्वप्न में कहा कि विद्वत्ता की पूर्णता भगवद् भक्ति में है। इस स्वप्न ने गहरा असर किया। ज्ञान का घमंड उतर गया। मन भगवत् भक्ति के रस में डूबने को बेताब हो उठा।

काशी से ओरछा लौटे तो जीवन बदल चुका था। राज वैभव, घर-परिवार, शास्त्रार्थ सबके प्रति पूर्ण अनासक्ति हो गई। मन वैराग्य रस से शुद्ध हो गया। हृदय गुरु चरणों में समर्पण के लिए तैयार था। इसी समय ओरछा में हितहरिवंश जी के शिष्य नवलदास आए। उनके भक्ति भरे सत्संग से प्रभावित होकर व्यास जी वृन्दावन जाने को तैयार हुए।

वृन्दावन प्राप्ति और गुरु कृपा

वृन्दावन की सीमा पर पहुंचकर वे सोचते रहते कि कब व्रजवासी बनूंगा। यमुना जी को प्रणाम किया, स्नान कर सेवाकुंज की ओर हितहरिवंश जी से मिलने चले। वृक्ष और लताओं को ऐसे भेंट करते मानो अपने प्रियजन हों। हृदय भक्ति से भरा था, आंखों में आनन्द के आंसू थे। वे गाते जा रहे थे -

"हम कब होहिंगे व्रजवासी । ठाकुर नन्दकिसोर हमारे, ठकुराइन राधा-सी । कब मिलिहं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी । वंशीवट की शीतल छाँह सुभग नदी जमुना-सी । जाको वैभव करत लालसा कर मीडत कमला-सी । इतनी आस 'व्यास' की पुजवह वृन्दाविपिन-विलासी ।"

हितहरिवंश जी राधावल्लभ का राग भोग तैयार कर रहे थे। व्यास जी का आगमन सुनकर पात्र रख दिया और आग बुझा दी। व्यास जी बोले कि आग क्यों बुझाई, भोजन बनता रहता। हितहरिवंश जी बोले मन बहुत चंचल है। इसे एक ही विषय में लगाना पड़ता है। श्री राधावल्लभ के चरणों में लगा देना ही ठीक है।

इस बात से व्यास जी बहुत प्रभावित हुए। हितहरिवंश जी ने दीक्षा दी। नाम व्यासदास हो गया। सेवाकुंज के पास मंदिर में रहकर भगवत् सेवा में लग गए। हितहरिवंश जी की कृपा से श्याम सुंदर के रस राज्य में वृन्दावन रस में प्रवेश हुआ।

वृन्दावन में प्रेम और समर्पण

उनका मन राधावल्लभ की प्रेम भक्ति में डूब गया। वृन्दावन के हर कण में आराध्य का दर्शन होने लगा। राधा रानी से विनती करते कि हे वृषभानु नंदिनी, आपकी चरण धूलि चाहिए। किसी कुंज के कोने में बैठकर राधा श्याम का नाम गाता रहूं। जिस धूलि को शिव सनकादि खोजते हैं, वही मस्तक पर चढ़ाऊं। आपका दर्शन करता रहूं और यश गान से वाणी को सरस बनाऊं।

ओरछा नरेश ने मंत्री भेजा उन्हें वापस लाने को। लेकिन व्यासदास कृष्ण रस में इतने डूबे कि प्राण जाएं पर वृन्दावन नहीं छोड़ेंगे। मंत्री ने हितहरिवंश जी से आज्ञा ली। व्यास जी को बहुत दुख हुआ। तीन दिन छिपे रहे। चौथे दिन गुरु ने खोजा तो मुख काला कर गधे पर सवार हो आए। बोले जिनके चरणों में शरण ली, वे बाहर निकाल रहे हैं तो काला मुख करके संसार लौटना ठीक है। हितहरिवंश जी उनकी गुरु निष्ठा और व्रज भक्ति से प्रसन्न हुए। ओरछा जाना रुक गया।

संतों के बीच जूठा प्रसाद खाते देख मंत्री को घृणा हुई। सोचा राज पुरोहित आचार भ्रष्ट हो गए। ओरछा जाना ठीक नहीं। व्यास जी को यही चाहिए था। मंत्री ने राजा को बताया। राजा भक्त हृदय थे। श्रद्धा बढ़ी। सोचा ऐसे भक्त का एक दिन भी ओरछा में आना पवित्र कर देगा। खुद वृन्दावन गए। बहुत आग्रह किया लेकिन व्यास जी नहीं माने। राजा ने पालकी में जबरदस्ती बैठाना चाहा। व्यास जी हर वृक्ष लता से गले लगकर बोले मेरा क्या पाप कि व्रज छोड़ना पड़ रहा। राजा मधुकर शाह चरणों पर गिरे, बोले जैसा चाहें वैसा करें। जाना रुक गया। व्यास जी ने राजा को दीक्षा दी, भजन का उपदेश दिया। पत्नी सुशीला भी ओरछा से आकर दीक्षा लेकर वृन्दावन में एकांत में भजन करती रहीं। व्यासदास जी की बात साकार हुई।

चमत्कार और लीला अनुभव

व्रज का चराचर उनके लिए प्रिय था, सब अपना था। वे व्रज रस के महापंडित, कृष्ण तत्व के ज्ञाता और राधा के चरण सेवक थे। वृन्दावन में कई चमत्कार हुए। एक बार रास उत्सव चल रहा था। बड़े रसिक संत मौजूद थे। नेत्रों से आनंद बह रहा था। राधा कृष्ण परिकर सहित नाच रहे थे।

राधारानी का नूपुर टूट गया। रस भंग होने का डर हुआ। व्यास जी ने यज्ञोपवीत तोड़कर नूपुर बांध दिया। मर्यादा रस मार्ग से हार गई। सन्तों ने उनकी बहुत प्रशंसा की।

एक बार ओरछा से रत्न जड़ित वंशी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए आई। वंशी मोटी थी। धारण कराते समय उंगली छिल गई। व्यास जी दुखी होकर कुंज से बाहर आए। थोड़ी देर में प्रभु ने खुद वंशी धारण कर ली।

एक बार जरकसी पाग आई। व्यास जी के कई प्रयत्न के बाद भी प्रभु ने नहीं पहनी। व्यास जी बोले आप बड़े चंचल हैं। मेरी बांधी पसंद नहीं तो खुद बांध लें। कुंज से बाहर आए। प्रभु ने पाग धारण कर ली। दर्शन करने वालों की प्रशंसा सुन व्यास जी परमानंद में डूब गए। चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई और जीवन सफल माना।

रचनाएँ और वृन्दावन तत्व

व्यास जी ने काव्य वाणी से वृन्दावन तत्व प्रकट किया। उनके वृन्दावन तत्व का आधार श्री राधारानी का नाम है। इस पवित्र नाम को कृष्ण अपनी वंशी में बार-बार बुलाते हैं। हरि गुण गान को कलियुग का सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना। अंत समय तक वृन्दावन में रहकर निकुंज लीला में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रजभाषा में भक्ति पूर्ण पद रचे। उनकी रचना 'व्यास वाणी' दो भागों में है - सिद्धांत और रस विहार।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

52.88% अंकों के साथ बनी नई मिसाल, डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री बने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के टॉपर

9 लाख से अधिक उम्मीदवारों की भीड़ में चमके कुछ ही सितारे

@ सौम्या चौबे

देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में गिनी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम सामने आते ही हजारों सपनों को दिशा मिल गई। इस वर्ष डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने 1,071 अंक प्राप्त कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। यह कुल 2,025 अंकों का लगभग 52.88 प्रतिशत है। दिलचस्प बात यह है कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पाने के लिए 50 प्रतिशत से थोड़ा अधिक अंक ही पर्याप्त साबित हुए। यही इस परीक्षा की कठिनाई और प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बताता है।इस बार 958 उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा ,भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य ग्रुप A और ग्रुप B सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया है। इन सफल उम्मीदवारों में 659 पुरुष और 299 महिलाएँ शामिल हैं।

डॉक्टर से प्रशासनिक अधिकारी बनने की कहानी

राजस्थान के कोटा से ताल्लुक रखने वाले अनुज अग्निहोत्री पेशे से डॉक्टर हैं। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने समाज के लिए कुछ व्यापक करने का सपना देखा और उसी ने उन्हें सिविल सेवा की ओर प्रेरित किया।अनुज के कुल 1,071 अंकों में से 867 अंक लिखित परीक्षा (मेन) में और 204 अंक इंटरव्यू में आए। यह अंक सुनने में भले ही आधे के आसपास लगते हों, लेकिन लाखों उम्मीदवारों के बीच यह एक असाधारण उपलब्धि है।सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है कि यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने की क्षमता, विश्लेषण, संतुलित दृष्टिकोण और व्यक्तित्व की परिपक्वता भी परखी जाती है।अनुज की सफलता यह भी दिखाती है कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और धैर्य से किसी भी लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है।

दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम

इस वर्ष दूसरा स्थान राजेश्वरी सुवे एम ने हासिल किया। उन्होंने 1,067 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 52.69 प्रतिशत है।राजेश्वरी वर्तमान में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इससे पहले तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की ग्रुप-I परीक्षा भी पास की थी।उनकी सफलता की कहानी भी प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पाँचवें प्रयास में यह परीक्षा पास की।चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई. की पढ़ाई करने वाली राजेश्वरी का वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र (Sociology) था।लगातार प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास ने आखिरकार उन्हें देश के शीर्ष उम्मीदवारों में जगह दिला दी।

तीसरे स्थान पर आकांक्ष धुल

तीसरे स्थान पर आकांक्ष धुल रहे, जिन्होंने कुल 1,057 अंक प्राप्त किए।आकांक्ष की सफलता यह दर्शाती है कि सिविल सेवा परीक्षा में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का संतुलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल चौथे स्थान पर राघव झुंझुनवाला रहे। उन्होंने कुल 1,042 अंक हासिल किए। वहीं पाँचवें स्थान पर ईशान भटनागर रहे। उनके कुल 1,038 अंक रहे।दिलचस्प बात यह है कि ईशान को इंटरव्यू में 215 अंक मिले, जो इस सूची में सबसे अधिक इंटरव्यू अंकों में से एक है।

सिर्फ अंक नहीं, व्यक्तित्व की भी परीक्षा

सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम मेरिट लिस्ट 2,025 अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है।इस तरह देखा जाए तो लिखित परीक्षा का महत्व अधिक है, लेकिन इंटरव्यू भी अंतिम रैंक तय करने में अहम भूमिका निभाता है। कई बार बहुत छोटे अंतर से रैंक ऊपर-नीचे हो जाती है। सिविल सेवा परीक्षा की कठिनाई का अंदाज़ा इसके आँकड़ों से लगाया जा सकता है।2025 में 9,37,876 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 5,76,793 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के बाद केवल 14,161 उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए। इसके बाद मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।अंततः केवल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया।यानी लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में से सिर्फ कुछ सौ ही इस मंज़िल तक पहुँच पाते हैं।

यह परीक्षा क्यों मानी जाती है सबसे कठिन

भारत में सिविल सेवा परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं।पहला कारण है इसका विस्तृत पाठ्यक्रम। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संबंध और समाज से जुड़े अनेक विषय शामिल होते हैं। दूसरा कारण है विश्लेषणात्मक प्रश्न। यहाँ सिर्फ तथ्यों को याद करना पर्याप्त नहीं होता। उम्मीदवार को विषय को समझना, उसका विश्लेषण करना और संतुलित उत्तर लिखना होता है।तीसरा कारण है लंबी प्रक्रिया। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम परिणाम तक लगभग एक साल का समय लगता है। इस दौरान उम्मीदवार को लगातार तैयारी बनाए रखनी पड़ती है।हर साल जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आता है तो देश भर के युवाओं को नई प्रेरणा मिलती है।अनुज अग्निहोत्री की कहानी बताती है कि किसी भी क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति अगर मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी करे तो वह इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है। राजेश्वरी सुवे एम की कहानी यह सिखाती है कि लगातार प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। पाँच प्रयासों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार देश की दूसरी रैंक हासिल कर ली।

महिलाओं की बढ़ रही है भागीदारी

इस वर्ष चयनित उम्मीदवारों में 299 महिलाएँ शामिल हैं। यह संख्या इस बात का संकेत है कि देश में प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।आज महिलाएँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रशासन, नीति निर्माण और शासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक सूची नहीं होता। यह लाखों युवाओं की मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी भी होता है। हर साल कुछ लोग सफल होते हैं और बहुत से लोग असफल भी होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हर उम्मीदवार कुछ नया सीखता है। जो सफल होते हैं वे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं और जो नहीं हो पाते, वे भी अपने अनुभव के साथ जीवन में नई दिशा तलाशते हैं।

सपनों से हकीकत तक का सफर

जब कोई युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, तब उसके सामने एक लंबा और कठिन रास्ता होता है।कई बार असफलता मिलती है, कई बार आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन जो लोग धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाते हैं।डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री और अन्य टॉपर्स की सफलता यही संदेश देती है कि सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करना ही सबसे बड़ा मंत्र है।

बहुत विनम्र और सहज हैं पूज्य कुमार स्वामी जी

मैं श्री कुमार स्वामी जी को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने सारे विश्व के सामने अथर्ववेद के मंत्र, तंत्र और विज्ञान को रखा है। यह विरासत केवल भारत के पास है, किसी और के पास नहीं है। मंत्र का विज्ञान मार्कण्डेय पुराण, श्रीमद्भागवत में है जो श्री कुमार स्वामी जी दे रहे हैं। स्वर्ण मंदिर की चर्चा 2014 के बाद हो रही है और अब एक लाख गठओं की गौशाला बनाने की बात हो रही है। अब देश विदेश में मंत्र विज्ञान की चर्चा हो रही है। यह विज्ञान हमारे ऋषियों ने भारत को दिया है। मैंने श्री कुमार स्वामी जी के समागमों में लोगों को रात्रि भर बैठे देखा है। जब हम नेपाल गए तो वहां बताया गया कि श्री कुमार स्वामी जी यहां जंगलों में जाकर साधना करते हैं। यह इतनी जनता जो यहां आई हुई है तो कोई न कोई बात तो है। इन्होंने पहले साधना की फिर सिद्धि मिली और उसके बाद प्रसिद्धि मिली। मान-सम्मान मिला लेकिन इतना होने के बाद भी श्री कुमार स्वामी जी बहुत ही विनम्र, सहज और सरल हैं। श्री कुमार स्वामी जी ने मंत्र विज्ञान के द्वारा करोड़ों लोगों का कष्ट निवारण किया है। यदि सीमा पर खड़ा हुआ सजग प्रहरी देश की रक्षा करता है तो श्री कुमार स्वामी जी संत समाज की रक्षा कर रहे हैं। इनके मन को स्वस्थ कर रहे हैं। इनके अवतरण दिवस पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज

आपके आशीर्वाद और प्ररेणा से कर रहा हूं मंदिरों का सौंदर्याकरण

परम श्रद्धेय, परम आदरणीय गुरु जी महाराज आज हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरा पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका कोटि-कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने स्वयं यहां आकर अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है। पिछले साल जब आप आए तो मैं किसी कारणवश आपके दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन आपकी प्रेरणा मुझे मिलती रही है। मैंने आपकी प्रेरणा से ही हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का सौंदर्याकरण और आधुनिकीकरण करने का जिम्मा लिया है। उना में माता चिंतपूर्णी के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सवा सौ करोड़ का बजट रखा गया है। इसी प्रकार नैना देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर तथा बाबा बालकनाथ मंदिर हमारी योजना में है। इन मंदिरों के नाम पर खेती और सोना चांदी के भंडार भी हैं जिनको हमने मंदिरों के लिए सुरक्षित रखा है। अब देखना यह है कि आपके आशीर्वाद से हमें कब और कितनी सफलता मिलती है। विगत समय में यहां प्राकृतिक आपदा से जानमाल का नुकसान हुआ था, बहुत सो संपत्तियां नष्ट हो गई थीं। आपके आशीर्वाद से धीरे-धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री जी
उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

प्रभु की तरफ लगन लगी आपके आने से

मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, सभी भक्त जन बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विभूति का आशीर्वाद मिल रहा है जिनके आशीर्वाद के लिए बहुत समय लग जाता है। आज ऊनावासियों के लिए बहुत शुभ दिन है। आप जैसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर सभी चलें। आपके आने से समाज में प्रभु की तरफ एक लगन लगी है। आपका आशीर्वाद हम सबके परिवारों पर बना रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री विवेक शर्मा जी विधायक, हिमाचल प्रदेश

सबके दुख निवारण के लिए करते हैं जप

आज पूज्य स्वामी जी का जन्म दिवस जिस भूमि पर मनाया जा रहा है और साथ ही यह संकल्प लिया जा रहा है कि यहां एक बहुत बड़ी गौशाला, गुरुकुल, मेडिकल सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम आदि योजनाओं को सफल बनाने का संकल्प भी लिया जा रहा है, वह भगवान श्रीकृष्ण और भगवान ब्रह्मा जी के संवाद की भूमि है। महाराज श्री सबके दुख निवारण के लिए जप करते हैं। मैंने तो जब भी इन्हें देखा है, जप में लीन देखा है। मैं यह कामना करता हूं कि ये शतायु हों, राधा रमण लाल जी इन पर कृपा करें और यहां स्वर्ण मंदिर बने।

आचार्य पद्मलोचन गोस्वामी जी
राधा रमण मंदिर

सनातन संस्कृति का संवर्धन कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी

महाराज जी ने हिमालय की कंदराओं में लंबे समय तक तपस्या करके मंत्रों को सिद्ध किया है। भारत की भूमि में और विश्व की बड़ी-बड़ी सीनेटों तथा पार्लियामेंटों में, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी महाराज जी को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। ये भारत की पुरातन संस्कृति के संवर्धन के कार्य में योगदान दे रहे हैं। भारत को विश्व गुर बनाने का पूज्य स्वामी का बहुत बड़ा प्रयास है। महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।

स्वामी ऋषेश्वरानंद जी महाराज
अध्यक्ष, चेतन ज्योति आश्रम

मंत्रों से विश्व को चमत्कृत किया है

आज हम ऐसे पूज्यश्री कुमार स्वामी जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं जिन्होंने मंत्रों से पूरे विश्व को चमत्कृत किया है। मैं राधा रानी सरकार से तथा बृज के अनंत तीर्थों से यह प्रार्थना करता हूं कि ये शतायु हों और जो इनक पावन संकल्प है वह भी संपूर्ण हो। महाराज श्री को अनंत कोटि शुभकामनाएं।

महामंडलेश्वर स्वामी निरंजन जी महाराज, हरिद्वार

UCC पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, क्या एक कानून की ओर बढ़ रहा है देश?

@ रिंकू विश्वकर्मा

एक देश, एक कानून की बहस फिर तेज, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से UCC चर्चा में

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में कानून और परंपराओं का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। यहां धर्म, संस्कृति और सामाजिक रीति-रिवाज केवल आस्था का विषय नहीं होते, बल्कि वे जीवन के हर छोटे-बड़े निर्णय को प्रभावित करते हैं। शादी से लेकर तलाक, विरासत से लेकर परिवार के अधिकारों तक ,कई मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग नियम लागू होते रहे हैं।लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस को फिर से तेज कर दिया। अदालत ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला संसद को लेना होगा।यह टिप्पणी केवल एक कानूनी बयान नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मुद्दे की ओर इशारा थी जो लंबे समय से भारतीय राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रहा है।

अदालत की टिप्पणी, फैसला संसद का

यह मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें 1937 के शरियत कानून की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन धाराओं के कारण मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के मामलों में पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते, जो संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही।बेंच ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विचार पहले भी कई बार सामने आ चुका है और अदालत ने पहले भी सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की बात कही है। लेकिन यह एक नीतिगत विषय है और कानून बनाना संसद का अधिकार है।अदालत ने साफ किया कि किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना अंतिम विकल्प होता है। अगर शरियत कानून की धाराओं को तुरंत रद्द कर दिया गया तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है।इसलिए अदालत ने संकेत दिया कि इस जटिल मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी विधायिका यानी संसद पर है।

संपत्ति का अधिकार धर्म नहीं, नागरिक अधिकार

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि संपत्ति में हिस्सा धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि नागरिक अधिकार है।उनका कहना था कि संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर शरियत कानून की कुछ धाराएं महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं, तो अदालत उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है।उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि शरियत कानून की कुछ धाराएं रद्द होती हैं, तो ऐसे मामलों में भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है।लेकिन अदालत ने इस पर सतर्क रुख अपनाया और कहा कि किसी एक कानून को हटाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसके स्थान पर स्पष्ट व्यवस्था हो।

शरियत कानून 1937 का इतिहास

जिस कानून पर विवाद खड़ा हुआ है, वह नया नहीं बल्कि लगभग एक सदी पुराना है।मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में मुसलमानों के निजी और पारिवारिक मामलों में इस्लामी कानून यानी शरियत लागू होगा।उस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के भीतर भी कई स्थानीय परंपराएं प्रचलित थीं। इससे अदालतों के फैसलों में एकरूपता नहीं रहती थी।इस समस्या को दूर करने के लिए 1937 का यह कानून बनाया गया, जिसके बाद विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, वक्फ और परिवार से जुड़े अन्य मामलों में शरियत के नियम लागू होने लगे।हालांकि यह कानून केवल निजी मामलों तक सीमित है। आपराधिक मामलों-जैसे चोरी, हत्या या अन्य अपराध—में पूरे देश में एक समान भारतीय दंड कानून ही लागू होता है।

महिलाओं के अधिकार का सवाल

समय के साथ-साथ इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा बहस महिलाओं के अधिकारों को लेकर हुई है।कई मामलों में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता, जिससे लैंगिक समानता का प्रश्न उठता है।महिला अधिकार संगठनों का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्तिगत कानून में ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जो महिलाओं के साथ भेदभाव करे। दूसरी ओर, कई धार्मिक संगठनों का कहना है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं और उनमें बदलाव करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।यही कारण है कि यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी बन जाता है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक ही कानून लागू हो।अभी भारत में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं-जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम आदि।अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इन सभी अलग-अलग कानूनों की जगह एक समान कानून लागू होगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने की सलाह दी गई है।हालांकि यह अनिवार्य नहीं बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांत है।

उत्तराखंड बना पहला राज्य

भारत में फिलहाल केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है।28 जनवरी 2025 को राज्य सरकार ने इसे लागू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।इस कानून के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए-किसी भी धर्म के रीति-रिवाज से शादी हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन न कराने पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है।विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष तय की गई है।शादी और तलाक के नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होंगे।लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।परिवार की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा।सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य समाज में समानता और पारदर्शिता लाना है।समान नागरिक संहिता का मुद्दा कई दशकों से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा है।कुछ लोग इसे संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं। उनका कहना है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून सामाजिक न्याय में बाधा बन सकते हैं।दूसरी ओर, कुछ समुदायों को यह डर भी रहता है कि समान कानून लागू होने से उनकी धार्मिक पहचान और परंपराओं पर असर पड़ सकता है।यही वजह है कि इस विषय पर अक्सर तीखी बहस देखने को मिलती है।

अदालत की संतुलित भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह का रुख अपनाया है, वह न्यायपालिका की संतुलित भूमिका को दर्शाता है।अदालत ने यह स्वीकार किया कि याचिका में उठाया गया भेदभाव का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इतने बड़े सामाजिक बदलाव का फैसला संसद को करना चाहिए। इस तरह अदालत ने एक तरफ महिलाओं के अधिकारों की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया और दूसरी तरफ कानून बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान भी किया।

देश किस मोड़ पर खड़ा है?

सवाल अब यह है कि क्या भारत वास्तव में समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ेगा।इसके लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि व्यापक सामाजिक संवाद भी जरूरी होगा।भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाना एक बड़ी चुनौती है जो समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दोनों के बीच संतुलन बना सके।लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि यह मुद्दा अब केवल बहस तक सीमित नहीं रहेगा।संभव है कि आने वाले वर्षों में संसद को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़े।भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। समान नागरिक संहिता की बहस भी इन्हीं मूल्यों के इर्द-गिर्द घूमती है।एक तरफ धार्मिक परंपराओं का सम्मान है, तो दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों की समानता का प्रश्न।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कानून, समाज और राजनीति को मिलकर भविष्य की दिशा तय करनी होगी।शायद आने वाले समय में यह तय होगा कि भारत अपनी विविधताओं को बनाए रखते हुए एक समान कानूनी ढांचे की ओर बढ़ता है या फिर वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार की राह तलाशता है।लेकिन इतना निश्चित है कि समान नागरिक संहिता की चर्चा अब और गहरी होने वाली है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

होली की अनोखी विरासत: तुर्की की मिठास से ब्रिटिश रंग तक

तुर्की की मिठास: गुजिया होली में कैसे बसी

होली के त्योहार में गुजिया की कुरकुरी परतें और अंदर की मीठी खोया-भरी सामग्री हर घर को खुशियों से भर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्वादिष्ट मिठाई असल में तुर्की की धरती से आई है? इतिहासकारों के मुताबिक, गुजिया का जन्म तुर्की के प्रसिद्ध डेजर्ट बक्लावा से जुड़ा हुआ है। बक्लावा एक लेयर्ड पेस्ट्री है, जिसमें पिस्ता, शहद और चीनी की परतें होती हैं, जो सदियों से तुर्की के अमीरों का पसंदीदा रहा। मध्य एशिया के रास्ते यह भारत पहुंची, शायद मुगल काल में, जब व्यापार और संस्कृति का आदान-प्रदान जोरों पर था। 13वीं शताब्दी के ग्रंथों में गुजिया जैसी कोई मिठाई का जिक्र मिलता है, जहां गुड़-शहद को गेहूं के आटे में लपेटकर सुखाया जाता था। धीरे-धीरे यह सांभल के समोसे जैसी दिखने लगी, लेकिन मीठी बनी रही। होली से इसका गहरा रिश्ता वसंत के आगमन से जुड़ा है, जहां मीठाई त्योहार की खुशी को दोगुना कर देती है। उत्तर भारत में यह चंद्रमा के आकार की बनाई जाती है, जो होली की रात चंद्रमा की तरह चमकती है। बिहार में इसे पेड़किया कहते हैं, गुजरात में घुगरा, जबकि महाराष्ट्र में करंजी। यह न सिर्फ खाने की चीज है, बल्कि परिवारों को जोड़ने वाली परंपरा भी। आजकल बाजार में रेडीमेड गुजिया मिल जाती है, लेकिन घर पर बनाई हुई का मजा ही अलग है। एक साधारण रेसिपी में आटा, घी, खोया, किशमिश, बादाम और काजू मिलाकर तलते हैं। लेकिन सोचिए, एक विदेशी स्वाद कैसे हमारी होली का हिस्सा बन गया? यह यात्रा हमें सिखाती है कि संस्कृतियां मिलकर नई परंपराएं कैसे बनाती हैं। गुजिया खाते हुए हम न सिर्फ मीठा चखते हैं, बल्कि सदियों की कहानी भी जीते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि खुशी बांटने में कोई सीमा नहीं होती।

भांग की कहानी: शिव का आशीर्वाद होली पर

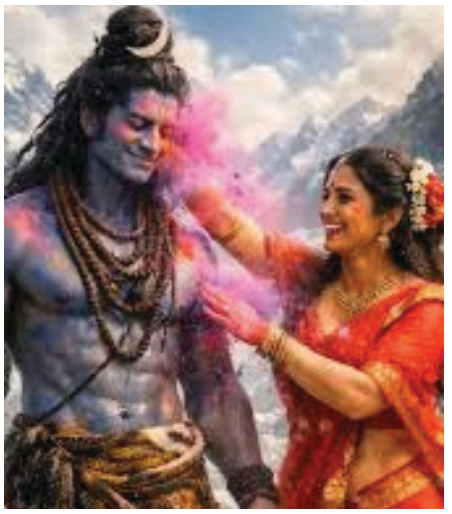

भांग की हरी-भरी पत्तियां होली की ठंडाई में मिलकर त्योहार को एक अलग ही रंग दे देती हैं। यह होली का पुराना साथी है, जो हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अथर्ववेद में भांग को पांच पवित्र पौधों में से एक बताया गया है, जो खुशी और मुक्ति लाती है। हिंदू मान्यताओं में भांग का सबसे गहरा रिश्ता भगवान शिव से है। कथा है कि शिव ने विष पिए हुए क्रोध को शांत करने के लिए भांग का सेवन किया, जिससे उन्हें शांति मिली। एक और कहानी में कामदेव ने शिव को भांग से लिपटा तीर चलाया, ताकि वे ध्यान से भटकें और जगत का भला हो। समुद्र मंथन की कथा में भी अमृत से भांग के पौधे उगे, जो शिव को समर्पित हुए। आयुर्वेद में भांग दर्द, पाचन और चिंता दूर करने की दवा रही, लेकिन होली पर यह उत्सव का प्रतीक बनी। मथुरा और वाराणसी जैसे शहरों में होली के दिन भांग वाली ठंडाई, लस्सी या गुड़िया बांटी जाती है, जो लोगों को नाचने-गाने का जोश देती है। ब्रिटिश काल में 1894 की हेम्प ड्रग्स कमीशन ने पाया कि मध्यम मात्रा में भांग हानिकारक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व वाली है। आज NDPS एक्ट के तहत भांग की पत्तियां वैध हैं, लेकिन फूल-राल पर पाबंदी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक पौधा कैसे धार्मिक आस्था और सामाजिक रिवाज का पुल बन गया। होली पर भांग पीते हुए लोग पुरानी यादें ताजा करते हैं, लेकिन संयम का संदेश भी मिलता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि खुशी के पीछे जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। भांग की यह दास्तान होली को सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि गहराई वाला उत्सव बनाती है।

रंगों का जादू: होली क्यों रंगीन बनी

होली को रंगों का त्योहार कहते हैं, क्योंकि ये रंग बसंत की बहार लाते हैं और अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। इसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जहां पुराणों में होलिका दहन की कथा मिलती है। राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने उसके बेटे प्रह्लाद को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार ने प्रह्लाद को बचाया। अगले दिन रंग खेलकर खुशी मनाई गई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है। दूसरी कथा कृष्ण-राधा की है, जहां कृष्ण ने गोपियों पर रंग डालकर प्रेम का इजहार किया। वृंदावन में आज भी लठमार होली इसी की याद दिलाती है। शुरू में रंग प्राकृतिक थे—तेजू के फूलों से लाल, हल्दी से पीला, चंदन से सफेद। ये रंग त्वचा के लिए सुरक्षित थे और प्रकृति से जुड़े थे। समय के साथ सिंथेटिक रंग आए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की चिंता बढ़ी। होली रंगों से न सिर्फ मजा आता है, बल्कि सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं—दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि रंग सिर्फ बाहर नहीं, दिलों में भी लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे नारद पुराण में होली का वर्णन है, जो वसंत के स्वागत का संकेत देता है। आज वैज्ञानिक नजरिए से रंगों का खेल तनाव कम करता है और एकता बढ़ाता है। लेकिन क्या हम पुरानी प्राकृतिक परंपरा को फिर से जगा सकते हैं? यह सवाल होली की रंगीनता को और गहरा बनाता है। रंगों के बिना होली अधूरी है, लेकिन इनके पीछे की कहानी हमें संस्कृति की विविधता सिखाती है।

पिचकारी का खेल: प्राचीन भारत का आविष्कार

पिचकारी से रंग छिड़कना होली का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन यह आविष्कार 1100 साल पुराना है। प्राचीन भारत में पिचकारी को पानी की सिरिंज कहा जाता था, जो पिस्टन पंप से काम करती थी। कर्नाटक के बेलूर के चेन्नकेशव मंदिर की 12वीं शताब्दी की दीवारों पर मादनिका देवी को पिचकारी से होली खेलते हुए उकेरा गया है। हम्पी के महानवमी दीब्बा मंदिर में भी 1513 ईस्वी की मूर्तियां महिलाओं को रंगीन पानी डालते दिखाती हैं। ये नक्काशी साबित करती हैं कि होली का यह खेल राजघरानों तक फैला था। शुरू में पीतल या लकड़ी से बनी पिचकारी हाथ से भरी जाती थी, जिसमें रंगीन पानी डाला जाता। राजस्थान के राजपरिवारों में ये तोहफे के रूप में दी जाती थीं। आधुनिक वाटर गन अमेरिका ने 1896 में पेटेंट किया, लेकिन भारत ने इसे सदियों पहले ईजाद कर लिया। होली पर पिचकारी से खेलना न सिर्फ मजा लाता है, बल्कि पुरानी परंपरा को जीवित रखता है। आज प्लास्टिक की सस्ती पिचकारियां मिलती हैं, लेकिन पुरानी शिल्पकारी की याद दिलाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी। पिचकारी का इतिहास होली को सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि तकनीकी विरासत बनाता है। खेलते हुए हम इतिहास को छूते हैं।

ब्रिटिश नजरों से होली: विदेशी दिलों में रंग

ब्रिटिश काल में होली को विदेशी आंखों से देखा गया, लेकिन कुछ अंग्रेजों ने इसमें हिस्सा भी लिया। 1837 में सर हेनरी फेन ने रणजीत सिंह के साथ होली मनाई, जहां रंग और पानी का खेल हुआ। कलाकारों ने इसे चित्रों में उतारा—जैसे विलियम कारपेंटर का 1850 का वॉटरकलर, जिसमें पुणे की सड़कों पर बच्चे रंग खरीदते दिखे। थॉमस ड्यूर ब्रॉटन की किताब में 'प्लेइंग द होली' नामक चित्र है, जहां महिलाएं पिचकारी से रंग छिड़क रही हैं। ब्रॉटन ने लिखा कि होली हिंदू कार्निवल जैसी है, जहां सड़कों पर गाने-बजाने और मजाक चलते हैं। महाराजा सिंधिया के कैंप में अंग्रेज अधिकारी रंग खेले, और होली के गीतों में उनका नाम आया। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी-कभी इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, क्योंकि अतिरिक्त उन्माद को अनुशासनहीन माना। फिर भी, होली की खुशी ने कुछ अंग्रेजों के दिल जीत लिए। यह दौर हमें दिखाता है कि त्योहार सीमाओं से परे हैं। ब्रिटिश चित्रों से होली की जीवंतता झलकती है, जो आज भी प्रेरणा देती है। क्या विदेशी नजरें हमारी परंपराओं को और मजबूत बनाती हैं? यह सवाल होली की सार्वभौमिक अपील को उजागर करता है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गूंजा भारत का विजय नाद, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 पर कब्जा

96 रन की जीत, 131 करोड़ का इनाम

भारत फिर बना टी-20 का सम्राट

@ आनंद मीणा

अहमदाबाद की रात, जब क्रिकेट ने लिखा नया इतिहास ,रविवार की वह रात भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे चमकदार पलों में से एक बन गई। गुजरात के अहमदाबाद स्थित विशाल और विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों दिल एक साथ धड़क रहे थे। मैदान में रोशनी, दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ,सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच रहे थे जिसे आने वाली पीढ़ियाँ लंबे समय तक याद रखेंगी। जब भारतीय कप्तान सूर्यकमार यादव ने ट्रॉफी को आसमान की ओर उठाया, तब पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और इंडिया-इंडिया के नारों से गूंज उठा। उस क्षण में सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक सपना था, जो करोड़ों भारतीयों ने देखा था।भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया।

ICC की प्राइज मनी,27.5 करोड़ रुपये

टी-20 विश्व कप जीतने के बाद भारत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से भी पुरस्कार राशि मिली।रिपोर्ट के अनुसार, भारत को विजेता के रूप में 3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 27.5 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई। वहीं फाइनल में हारने वाली न्यूजीलैंड टीम को 1.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 14.7 करोड़ रुपये मिले। हालांकि इस बार ICC ने आधिकारिक रूप से पहले से प्राइज मनी की घोषणा नहीं की थी। आमतौर पर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही यह जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है।भारत बना तीन बार टी-20 विश्व चैंपियन इस जीत के साथ भारत ने टी-20 क्रिकेट के इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।भारत अब तीन बार टी-20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में भी यह खिताब जीता था। पहली बार 2007 में भारत ने South Africa में खेले गए पहले टी-20 विश्व कप में जीत हासिल की थी। उस समय टीम के कप्तान थे धोनी,दूसरी बार 2024 में भारत ने वेस्ट इंडीज में आयोजित टूर्नामेंट में खिताब जीता।और अब 2026 में भारत ने एक बार फिर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली।इस जीत के साथ भारत टी-20 विश्व कप का खिताब लगातार दो बार जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है।

BCCI का बड़ा इनाम, 131 करोड़ का सम्मान

इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया। यह राशि केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। इसमें टीम के सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा। दरअसल, किसी भी बड़ी जीत के पीछे सिर्फ मैदान पर खेल रहे खिलाड़ी ही नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे काम कर रही पूरी टीम की मेहनत शामिल होती है।

BCCI ने अपने बयान में कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक है और इस उपलब्धि में योगदान देने वाले हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए।

घरेलू मैदान पर पहली बार विश्व कप जीत

इस जीत की एक और खास बात यह रही कि भारत ने पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टी-20 विश्व कप जीता।अहमदाबाद के स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हजारों दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, जबकि करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर मैच देख रहे थे।मैच के आखिरी ओवर में जब जीत तय हुई, तब पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। तिरंगे लहराए गए, आतिशबाजी हुई और खिलाड़ियों को कंधों पर उठाकर सम्मान दिया गया।यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत और निरंतरता का प्रतीक थी।फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ खेलते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। भारत के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा।अंततः न्यूजीलैंड की पूरी टीम लक्ष्य से 96 रन पीछे रह गई और भारत ने शानदार जीत दर्ज की।

जश्न के अलग-अलग रंग

टी-20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी देखने लायक था। मैदान में खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को गले लगाया, तिरंगे के साथ दौड़ लगाई और ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।कप्तान का जश्न सबसे खास रहा। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में स्थित ऐतिहासिक बावड़ी Adalaj Stepwell में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया।करीब 500 साल पुरानी इस ऐतिहासिक बावड़ी की भव्य वास्तुकला और विश्व कप ट्रॉफी का संयोजन एक अद्भुत दृश्य बन गया। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं।

क्रिकेट प्रेमियों में उत्सव का माहौल

भारत की इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया।दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई और लखनऊ से जयपुर तक हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और लोग तिरंगा लेकर नाचते-गाते नजर आए।सोशल मीडिया पर भी बधाइयों की बाढ़ आ गई। क्रिकेट प्रेमियों से लेकर बॉलीवुड सितारों और राजनीतिक नेताओं तक सभी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दीं।भारत की यह जीत केवल एक टूर्नामेंट जीतने की कहानी नहीं है। यह उस लंबे सफर की कहानी है जिसमें मेहनत, अनुशासन और टीम भावना शामिल है।भारतीय क्रिकेट ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, वह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है।टीम की फिटनेस, रणनीति और युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा ने भारत को क्रिकेट की दुनिया में एक नई पहचान दी है।इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी भारत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा।नई प्रतिभाओं का उदय, मजबूत घरेलू ढांचा और अनुभवी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भारतीय क्रिकेट को लगातार आगे बढ़ाने में मदद करेगा।अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक रात ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि भारत की भावना है।जब टीम इंडिया जीतती है, तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं जीतते बल्कि पूरा देश जीतता है। टी-20 विश्व कप 2026 की यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुकी है। और जब भी इस अध्याय को पढ़ा जाएगा, उसमें अहमदाबाद की वह रात, खिलाड़ियों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों का गर्व हमेशा चमकता रहेगा।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

बोलो दोस्त क्या सुनना चाहते हो?

जब एक दोस्त ने कहा कि
ऐसे मुश्किल समय में

तुम्हारी कविताएँ कहाँ हैं?
तब कविताओं की बेबसी का एहसास हुआ!

ये तो बात साफ़ थी कि
दोस्त कुछ सुनना चाहता था,

ज़ाहिर-सा कुछ
इसलिए मेरी क़लम के आलस ने

उसी से पूछ लिया...
बोलो दोस्त, क्या सुनना चाहते हो?

क्या उम्मीद सुनोगे?
कि बहार फिर से आएगी

वसंत आएगा दबे पाँव :
सेमल का गुलदस्ता लिए

या चाहते हो कि
घोंप दूँ तुम्हारी आत्मा में कुछ नुकीले सवाल?
कि क्यों
क्रम में और भ्रम में

दुआ, दवा से पहले आती है?
अस्पताल की नींव से पहले

दुआओं के काल्पनिक पत्थरों पर क्यों
सोने का पानी चढ़ता है?

और संवेदनाओं के क़त्ल में
क्यों अव्वल आता है हमेशा

तुम्हारा-मेरा मध्यवर्ग?
जो रात के खाने के बाद मीठे में

प्राइम-टाइम पर परोसी पुलिस की लाठी को
'न्याय' कह देता है!

बोलो दोस्त क्या सुनना चाहते हो?
क्या सच सुनोगे कि

सच अब कड़वा भी नहीं रहा
'पोस्ट-ट्रुथ' के दौर में

वह बाज़ार में आया एक दुर्लभ बेस्वाद फल है
जो पूँजीपतियों के हिस्से आना तय है

और तय है कि उसका भुगतान ग़रीब की चमड़ी से हो
जो पिटते-पिटते ही सही, पर घर पहुँचना चाहे

तय है कि इनकी मजबूरी को तुम और मैं
आंचलिकता की टिप्पणियों से विदा करें

तय है कि तमाशा देख, आह निकालने के बाद
घर में बंद हमें आवारा कुत्तों से जलन हो

तय है कि क़ुदरत अपने बचाव में कुछ पासे फेंके
हमारी कल्पनाओं की दुनिया

जो हम चिल्लरों, काग़ज़ों से चलाते हैं
वह ढह जाए

तय है कि राशन की क़तारों में खड़े हुए
मेरी रीढ़ झुकना चाहे

फिर से बंदर बनने के लिए
और मुक्त हो जाना चाहे

कविताओं की सभ्यता के इस डरावने खेल से
बोलो दोस्त, क्या तुम यहीं सुनना चाहते थे?

ये एक रात का साया है

ये एक रात का साया है
और भूख ने घेरा है

दूर वादियों से भेजे हैं
आवाज़ के नगीने

जो कानों के हवाले
यूँ होते हैं

कि जैसे राशन मिला हो उन्हें
बड़ी तन्हा-सी ख़ुराक है

जिसे बाँटने की ख़्वाहिश में
कई-कई दफ़ा

तस्वीर बना यूँ छुपाया है
जैसे मिठाई हों

ताल से परछाइयाँ
ये एक रात का साया है

और सवालों ने घेरा है
एक खिड़की के बारे में सोचा है

एक दराज़ के बारे में भी
एक किताब ज़रूर रखी होगी वहाँ

शायद एक पन्ना भी मुड़ा हुआ हो
सोचती हूँ कि

उसके मुड़े हुए होने की उम्र क्या होगी?
कुछ जान लेने की उम्र क्या होगी?

क्या वह इलहाम अभी भी ज़िंदा होगा?
या उसी का सिरा पकड़

कोई नया पन्ना मोड़ा होगा?
और मुमकिन होने की छोटी-सी फ़ेहरिस्त में

वो खिड़की, वो दराज़
वो पन्ना, वो किताब

कभी निकलेंगे क्या
सपनों से सिरहाने की ओर?

ये एक रात का साया है
और एक धुन ने घेरा है

मैंने सुना है कि
नींद में बुदबुदाओ तो

पहाड़ गूँजते हैं?
और कहते हैं कि

जंगलों की आग
सूखे पत्तों पर गिरी

जुनून की चिंगारियों से बुझती है
ये अफ़वाह भी है कि

चमोली का भूकंप असल में
एक शाइर का इज़हार था

जो अकेलेपन को प्यार मान बैठा
और धरती को अपनी जागीर मान

कपकोट की ज़मीन को
कर आया हवाले भूस्खलन के

बहरहाल,
अब ये एक रात का साया है

और धड़कन को भूल जाने की इच्छा का
मारा है

साँस को आदतों में शुमार करने का

एक हिदायत भरा ख़त मिला है
और मुझसे कहा गया है कि

ख़त के जवाब में
मैं सच्चे मन से लिख भेजूँ कुछ ऐसी जवाबी
चिट्ठी :

"ठीक है। आज ही समझदारी की दवा का
परचा बनवाकर आती हूँ। आप चिंता मत
करना।

रात के साये का वक़्त होते ही एक खा लूँगी।
—आपकी प्यारी

अवचेतना" तो,

ये एक रात का साया है
और धुँधलके ने घेरा है...

प्रकृति करगेती

(नई पीढ़ी की लेखिका। दो कविता-संग्रह 'शहर और शिकायतें' (2017), 'दो ध्रुवों के बीच' (2023) और एक कहानी-संग्रह 'ठहरे हुए से लोग' (2022) प्रकाशित)

बालेन शाह का धमाका: 4 साल में नेपाल की सत्ता कैसे हिलाई, दिग्गज क्यों गिरे, भारत से रिश्ते पर नई बहार?

रैपर से राजा तक: बालेन की तेज चढ़ाई

नेपाल की राजनीति में बालेन शाह का नाम आज हर जुबान पर है। महज 35 साल के इस युवा ने 4 साल में जो रफ्तार पकड़ी, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। 2013 में रैप गाने से मशहूर हुए बालेन, जो असल नाम है बलेन्द्र शाह, ने अपनी आवाज से भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ ललकार मचाई। फिर 2022 में काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा, वो भी बिना किसी पार्टी के समर्थन के। बस एक चलने वाली छड़ी का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे और 61,767 वोट हासिल कर जीत गए। पुराने दिग्गजों को धूल चटा दी। मेयर बनते ही उन्होंने सड़कों की सफाई से लेकर कचरे के ढेर हटाने तक काम शुरू कर दिया। लोग कहते हैं, बालेन ने दिखाया कि शहर को साफ-सुथरा बनाने का मतलब सिर्फ बातें नहीं, काम है। उसी साल उन्होंने राष्ट्रिय स्वतंत्रता पार्टी (आरएसपी) बनाई, जो युवाओं की आवाज बनी। 2025 के बड़े आंदोलन के बाद 2026 के आम चुनाव में बालेन ने झापा-5 सीट से ताल ठोकी। ये सीट तो पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का गढ़ थी। लेकिन बालेन ने वहां भी लीड ले ली। उनकी पार्टी आरएसपी को 45 सीटें मिल चुकी हैं और 74 पर बढ़त है। ये जीत जनरेशनल चेंज की निशानी है। बालेन की ताकत उनकी सोशल मीडिया की ताकत में है – 3.5 मिलियन फॉलोअर्स। वे सीधे लोगों से जुड़ते हैं, बिना मीडियम के। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, यहां तक कि भारत से मास्टर्स डिग्री ली। लेकिन राजनीति में उनकी अपील युवाओं की नाराजगी से आई। भ्रष्टाचार से तंग जनता ने उन्हें नया चेहरा माना। ये चढ़ाई सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत और समय की मांग है। बालेन साबित कर रहे हैं कि नई पीढ़ी पुरानी दीवारें तोड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चढ़ाई लंबी चलेगी?

पुराने दिग्गजों की लुढ़कन: क्यों भारी पड़ी भ्रष्टाचार की बोझ?

नेपाल के पुराने नेता अब क्यों हार रहे हैं, ये सवाल हर नागरिक के मन में घूम रहा है। पिछले 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके, कोई भी पूरा कार्यकाल नहीं निभा पाया। ये अस्थिरता ने जनता को थका दिया। के.पी. शर्मा ओली जैसे दिग्गज, जो चार बार पीएम बने, अब अपनी ही सीट पर हार गए। वजह? भ्रष्टाचार, घमंड और लोगों से कट जाना। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) पर भ्रष्टाचार के कई इल्जाम लगे, लेकिन वे सुधार नहीं लाए। जनता कहती है, नेता तो सत्ता के चक्कर में लगे रहे, लेकिन सड़कें, नौकरियां, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें ठप। ओली ने नए चेहरों का मजाक उड़ाया, कहा उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। लेकिन वोटों ने जवाब दे दिया। पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन, जो सालों से सत्ता घेरे हुए थे, अब जनता की नजरों से गिर गईं। युवा रोज 2,300 लोग देश छोड़कर नौकरी के लिए जा रहे, क्योंकि घर में मौके ही नहीं। ये हार सिर्फ चुनाव की नहीं, सिस्टम की नाकामी की है। पुराने नेता भूल गए कि राजनीति सेवा है, न कि परिवारवाद। भ्रष्टाचार के घोटालों ने लोगों का भरोसा तोड़ा। अब नई पार्टियां जैसे आरएसपी एंटी-करप्शन का झंडा उठा रही हैं। ये हार सोचने पर मजबूर करती है – क्या पुरानी व्यवस्था अब फिट नहीं रही? जनता ने साफ कह दिया, बदलाव चाहिए। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ गुस्से का नतीजा है या सोची-समझी मांग? नेपाल को स्थिरता की जरूरत है, वरना ये लुढ़कन और गहरी हो सकती है।

2025 का तूफान: युवाओं ने कैसे हिलाई सत्ता की चूलें?

2025 का साल नेपाल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जनरेशन जेड के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जो बवंडर मचाया, उसने पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। सितंबर में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, खराब शासन और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ थे। कम से कम 77 लोग मारे गए, जब पुलिस ने दमन किया। ये आंदोलन ओली सरकार के खिलाफ था, जो बहुमत वाली गठबंधन चलाती थी। युवा चिल्ला रहे थे – अच्छा शासन दो, भ्रष्टाचार बंद करो। सोशल मीडिया ने इन्हें जोड़ा, दुनिया भर के युवा आंदोलनों से प्रेरणा ली। नेपाल में तो ये इतना तेज था कि ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन जनता ने कहा – अब स्थायी बदलाव चाहिए। ये पहला चुनाव था 2025 के विद्रोह के बाद। बालेन शाह जैसे नए चेहरे इसी लहर पर सवार हुए।

उन्होंने अंतरिम सरकार जॉइन करने से इनकार कर दिया, ताकि पूरा कार्यकाल पूरा करें। ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं, वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा था – बांग्लादेश से लेकर अन्य देशों तक युवा सिस्टम बदलना चाहते हैं। नेपाल में ये सफल रहा, क्योंकि जनता थक चुकी थी पुरानी पार्टियों के चक्रव्यूह से। अब 2026 की जीत उसी तूफान का फल है। लेकिन सोचिए, क्या ये युवा ऊर्जा स्थिर सरकार बना पाएगी? या ये सिर्फ शुरुआत है एक लंबी लड़ाई की? नेपाल के युवाओं ने साबित किया कि आवाज बुलंद हो तो सत्ता भी झुक जाती है।

भारत-नेपाल की दोस्ती: बालेन की जीत से क्या नई दिशा?

बालेन शाह की जीत भारत के लिए सोचने का विषय है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, खुली सीमा, सांस्कृतिक रिश्ते – सब कुछ गहरा बंधन। लेकिन बालेन का राष्ट्रवादी रुख कुछ सवाल खड़े करता है। वे कहते हैं, भारत और चीन दोनों से मजबूत, लेकिन स्वतंत्र रिश्ते। 2023 में उन्होंने बड़ा नेपाल का नक्शा दिखाया, जिसमें भारत के कुछ राज्य शामिल थे – जैसे उत्तराखंड, हिमाचल। 2025 में सोशल मीडिया पर भारत, अमेरिका, चीन को कोसा। कालापानी, लिपुलेख जैसे बॉर्डर विवादों पर उनका स्टैंड सख्त है। ये भारत के लिए चुनौती हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, रिश्ते मजबूत रहेंगे। क्यों? क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। बिजली, व्यापार, विकास परियोजनाएं – सब भारत से जुड़े।

नेपाली युवा गल्फ देशों में कमाते हैं, लेकिन वो भी भारत की विदेश नीति से प्रभावित। बालेन की आरएसपी सेंट्रिस्ट है – वैश्विकरण समर्थक, लिबरल। वे आर्थिक विकास चाहते हैं, नौकरियां। भारत को पड़ोस पहले नीति से नया नेतृत्व से जुड़ना चाहिए, ताकि चीन का असर न बढ़े। पोखरा एयरपोर्ट, काठमांडू-तिब्बत रेल जैसी चीनी परियोजनाएं चिंता की हैं, खासकर सिलिगुड़ी कॉरिडोर के लिए। लेकिन बालेन की जीत नई शुरुआत का संकेत है। सांस्कृतिक करीबी बरकरार रहेगी। भारत को सतर्क रहना है, लेकिन सहयोग बढ़ाना चाहिए। क्या ये जीत रिश्तों को मजबूत करेगी या तनाव लाएगी? समय बताएगा, लेकिन आशा है कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़ें।

आगे की जद्दोजहद: बालेन के सपनों पर क्या पड़ेगी कसौटी?

बालेन शाह अब सत्ता के करीब हैं, लेकिन राह आसान नहीं। नेपाल को स्थिर सरकार चाहिए, जो सालों से नहीं मिली। आरएसपी को बहुमत मिला है, लेकिन गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। बालेन को भ्रष्टाचार रोकना, नौकरियां देना, अर्थव्यवस्था सुधारना होगा। युवा चाहते हैं बाजार-मैत्रीपूर्ण नीतियां, लेकिन अमल मुश्किल। बॉर्डर मुद्दे, चीन का दखल – ये बाहरी चुनौतियां हैं। अंदरूनी तौर पर, उनका गुस्सैल स्वभाव काम आएगा या अड़चन?

मेयर के तौर पर उन्होंने काम दिखाया, लेकिन पीएम बनना बड़ा जिम्मेदारी। विशेषज्ञ कहते हैं, बालेन को सिस्टम सुधारना होगा, वरना पुरानी गलतियां दोहरा दें। लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं। ये जीत वैश्विक ट्रेंड दिखाती है – युवा नेता बदलाव ला सकते हैं। नेपाल अगर स्थिर हुआ, तो भारत-नेपाल रिश्ते और मजबूत होंगे। बालेन की कहानी प्रेरणा है – मेहनत से कुछ भी हासिल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वे वादे निभा पाएंगे? जनता देख रही है। अगर सफल हुए, तो नेपाल नया मॉडल बनेगा। ये सफर अभी शुरू हुआ है, अंत दिलचस्प होगा।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक की मांग: कर्नाटक से आंध्र तक क्यों गूंज रही आवाजें

नई शुरुआत: दो राज्यों में बच्चों के लिए बड़ा फैसला

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात तेज हो गई है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026-27 के बजट में ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होगा। उनका कहना था कि मोबाइल फोन का बढ़ता चलन बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है, और यह कदम बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाएगी, और यह नियम 90 दिनों के अंदर लागू हो सकता है। आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि इसके लिए मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियों से बात हो रही है। ये फैसले भारत में पहली बार ऐसे हैं जब राज्य स्तर पर इतनी सख्ती की जा रही है। आर्थिक सर्वे 2025-26 ने भी केंद्र सरकार से उम्र के आधार पर सोशल मीडिया लिमिट लगाने की सलाह दी थी। इन घोषणाओं से पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह बहुत जल्दबाजी वाला फैसला है। कर्नाटक में 'मोबाइल बिदि, पुस्तक हिदि' जैसी मुहिम चल रही है, जो बच्चों को फोन छोड़कर किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आंध्र में एक मंत्री समूह इस पर काम कर रहा है, जिसमें 13 से 16 साल के किशोरों के लिए भी नियम बनाने की बात है। ये कदम दिखाते हैं कि राज्य सरकारें अब बच्चों के डिजिटल दुनिया से निपटने को लेकर गंभीर हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नियम कैसे लागू होंगे और क्या वे वाकई काम करेंगे। कुल मिलाकर, ये घोषणाएं एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हैं, जहां बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी जा रही है।

छिपे खतरे: सोशल मीडिया बच्चों की सेहत पर क्यों बन रहा बोझ

बच्चों के लिए सोशल मीडिया के खतरे अब छिपे नहीं रह गए हैं, और यही वजह है कि कर्नाटक से आंध्र प्रदेश तक बैन की मांग तेज हो रही है। आर्थिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, युवाओं में डिजिटल लत तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता, डिप्रेशन और कम आत्मसम्मान का कारण बन रही है। एक पुरानी सर्वे में पाया गया कि 14 से 16 साल के 90 फीसदी बच्चों के घर में स्मार्टफोन है, और 76 फीसदी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इससे ध्यान भटकना, पढ़ाई में कमी और नींद की समस्या जैसी परेशानियां बढ़ गई हैं। साइबर बुलिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां बच्चे ऑनलाइन ताने-मजाक से मानसिक तनाव में फंस जाते हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है, जैसे चिड़चिड़ापन और अकेलापन। आंध्र में भी इसी तरह की चिंता है, जहां आईटी मंत्री ने कहा कि डिजिटल उत्पीड़न से बच्चों को बचाना जरूरी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सोशल मीडिया की डिजाइन ही ऐसी है जो ज्यादा समय बिताने पर मजबूर कर देती है, जैसे लाइक्स और कमेंट्स का चक्कर। भारत में 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और इसमें बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। एक स्टडी में देखा गया कि सोशल मीडिया से जुड़ी लत छात्रों में तनाव और डिप्रेशन को 30 फीसदी तक बढ़ा देती है। ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि क्या बैन ही एकमात्र रास्ता है। कई माता-पिता बताते हैं कि बच्चे स्कूल से लौटते ही फोन में खो जाते हैं, जिससे परिवार का समय कम हो रहा है। कुल मिलाकर, ये खतरे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते, और राज्य सरकारें इन्हें रोकने के लिए सक्रिय हो रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ रोक से समस्या हल हो जाएगी, या और कदम भी उठाने पड़ेंगे।

वैश्विक लहर: भारत भी जुड़ रहा बच्चों की सुरक्षा की इस जंग में

दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की बहस चल रही है, और कर्नाटक-आंध्र के फैसले इसी लहर का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में पहली बार कानून बनाया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट ब्लॉक करने पड़ते हैं। वहां के सर्वे में 50 फीसदी से ज्यादा युवाओं ने साइबर बुलिंग की शिकायत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत से भी 15 साल से कम उम्र के लिए बैन लगाने की अपील की, और कहा कि जी7 की मीटिंग में इस पर बात हो। स्पेन, डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे देश भी इसी दिशा में सोच रहे हैं। मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि एआई और डिजिटल दुरुपयोग से बच्चों को बचाना वैश्विक जिम्मेदारी है। भारत में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सोशल मीडिया कंपनियों से उम्र आधारित लिमिट पर चर्चा कर रहा है। आर्थिक सर्वे ने भी सुझाव दिया कि साधारण फोन या फिल्टर वाले टैबलेट को बढ़ावा दिया जाए। ये वैश्विक ट्रेंड दिखाते हैं कि सोशल मीडिया के फायदे के साथ-साथ खतरे भी बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में लाखों अकाउंट बंद हुए, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों ने फर्जी आईडी से बचने का रास्ता निकाल लिया। भारत के संदर्भ में यह और मुश्किल है, क्योंकि यहां इंटरनेट यूजर्स एक अरब के करीब हैं। कर्नाटक जैसे टेक हब में यह फैसला खास तौर पर अहम है, जहां बच्चे जल्दी डिजिटल दुनिया में कूद पड़ते हैं। आंध्र का कदम भी इसी वैश्विक सोच से प्रेरित है, जहां मंत्री समूह कंपनियों से सलाह ले रहा है। कुल मिलाकर, ये फैसले भारत को वैश्विक मंच पर बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत बना सकते हैं। लेकिन क्या हम ऑस्ट्रेलिया की तरह सफल होंगे, यह समय बताएगा। यह लहर सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल दुनिया को कैसे संतुलित बनाया जाए।

मुश्किलें और राय: विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस बैन पर

सोशल मीडिया बैन का विचार अच्छा लगता है, लेकिन लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। टेक कंपनियां कहती हैं कि राज्य स्तर पर अलग-अलग नियम बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि कर्नाटक में 16 साल की लिमिट है तो आंध्र में 13 साल की। मेटा की ओर से कहा गया कि बैन से बच्चे असुरक्षित साइट्स पर चले जाएंगे। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे ज्यादा सख्त बताया, और कहा कि इससे लड़कियों का डिजिटल गैप बढ़ सकता है, क्योंकि परिवार उन्हें फोन से दूर ही रखना चाहेंगे। बच्चे अधिकार समूहों का मानना है कि बैन से ज्यादा जागरूकता जरूरी है, जैसे माता-पिता को गाइड करना और स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी सिखाना। बैंगलोर के चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट के डायरेक्टर एनवी वासुदेव शर्मा ने कहा कि बच्चे छोटी उम्र से फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से वे जिम्मेदार बन सकते हैं। कर्नाटक में मोबाइल एडिक्शन पर मीटिंग हुई, जहां सुझाव आया कि टीचर ट्रेनिंग और काउंसलर बढ़ाए जाएं। आंध्र में भी इसी तरह, कंपनियों से उम्र चेक करने के तरीके पर बात हो रही है, लेकिन फर्जी आईडी का डर है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैन अकेला काफी नहीं, प्लेटफॉर्म को सेफ्टी फीचर्स डालने चाहिए। आर्थिक सलाहकार ने कहा कि उम्र आधारित पॉलिसी से डिजिटल लत कम हो सकती है, लेकिन शिक्षा के बिना यह अधूरा है। ये राय संतुलित नजरिया देती हैं, जहां खतरे को मानते हुए समाधान की तलाश है। कुल मिलाकर, बहस यह है कि सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, बिना आजादी छीने। यह विचार-विमर्श भविष्य के लिए रास्ता साफ कर सकता है।

भविष्य की दिशा: ये बैन क्या बदलाव लाएंगे बच्चों की दुनिया में

कर्नाटक और आंध्र के इन फैसलों से बच्चों की डिजिटल जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आगे क्या होगा, यह सवाल कई हैं। अगर बैन लागू हो गया, तो स्कूलों में किताबें और खेलकूद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जैसा कर्नाटक की मुहिम में हो रहा है। आंध्र में 13-16 साल के लिए हल्के नियम आ सकते हैं, जो किशोरों को जिम्मेदारी सिखाएंगे। केंद्र स्तर पर अगर एक समान कानून बना, तो पूरे देश में एकरूपता आएगी। विशेषज्ञ सुझाते हैं कि सस्ते फोन या एजुकेशन टैबलेट को प्रोत्साहन दिया जाए, जहां कंटेंट फिल्टर हों। इससे बच्चे सुरक्षित तरीके से सीख सकेंगे। लेकिन चुनौती यह है कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच बढ़ रही है, वहां जागरूकता कैसे फैलेगी। माता-पिता की भूमिका भी अहम होगी, जो बच्चों को फोन देने से पहले सोचेंगे। वैश्विक उदाहरण से सीखते हुए, भारत अपनी नीति बना सकता है, जो मानसिक सेहत को प्राथमिकता दे। आर्थिक सर्वे ने चेतावनी दी कि लत से उत्पादकता घट रही है, इसलिए ये कदम लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर बैन सख्ती से लागू न हुआ, तो सिर्फ कागजी रह जाएगा। कुल मिलाकर, यह बदलाव बच्चों को बेहतर कल दे सकता है, जहां टेक्नोलॉजी दोस्त बने, दुश्मन न। सोचिए, अगर बच्चे ज्यादा समय पार्क में बिताएं, किताबें पढ़ें, तो उनकी जिंदगी कितनी रंगीन हो जाएगी। ये फैसले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रगति के साथ सुरक्षा कैसे जोड़ी जाए।

इजरायल-ईरान जंग के बीच भारत को तेल राहत: अमेरिका की 30 दिन की छूट से रूसी क्रूड बिना पेनाल्टी, लेकिन पीछे का राज क्या?

मध्य पूर्व का संकट: तेल कीमतों पर छाई काली बादल

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया है। हाल ही में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी जैसी कार्रवाई की, जिससे मध्य पूर्व से तेल की सप्लाई में बड़ा खलल पड़ा। यह इलाका दुनिया के 40 प्रतिशत से ज्यादा कच्चे तेल का रास्ता है, और भारत जैसे देश जो यहां से 40 प्रतिशत तेल आयात करते हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरानी ठिकानों पर हमलों के बाद तेल की कीमतें 5 प्रतिशत चढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो कीमतें 150 डॉलर तक जा सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटक सकती है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। 5 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने घोषणा की कि भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की छूट मिलेगी। यह छूट उन रूसी तेल के कार्गो पर लागू है जो समुद्र में फंसे हुए हैं, यानी 5 मार्च से पहले लोड हुए जहाजों का तेल। भारत के सरकारी रिफाइनरी जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब इन 20 मिलियन बैरल के आसपास तेल को खरीद सकेंगे। यह कदम ईरान संकट के बीच सप्लाई चेन को सहारा देने का प्रयास है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी समाधान है या कुछ बड़ा बदलाव? भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का तेल स्टॉक है, इसलिए यह छूट ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से सांस लेने जैसी है। वैश्विक स्तर पर कतर जैसे देशों के मंत्री चिंता जता रहे हैं कि तेल कीमतों का उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे खींच सकता है। कुवैत जैसे गल्फ देश उत्पादन काटने लगे हैं, और रूस जैसे देशों को फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी मांग बढ़ गई है। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है, और भारत जैसे उभरते देशों को अपनी रणनीति कैसे बदलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर, यह छूट तात्कालिक राहत तो देगी, लेकिन लंबे समय के लिए भारत को वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता कम करनी होगी।

अमेरिका का उलटफेर: रूसी तेल पर छूट क्यों, जब सैंक्शन इतने सख्त थे?

अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूसी तेल पर सख्त सैंक्शन लगाए थे, और भारत जैसे बड़े खरीदारों पर 25 प्रतिशत का आयात टैरिफ भी ठोंका था। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और कड़ा किया, कहते हुए कि सस्ता रूसी तेल खरीदकर भारत रूस को युद्ध की फंडिंग कर रहा है। भारत ने जनवरी 2026 में खरीद कम करके टैरिफ से बच गया और अमेरिका के साथ अस्थायी व्यापार समझौता किया। फिर अचानक 2026 के मार्च में यह 30 दिन की छूट क्यों? वजह साफ है- इजरायल-ईरान जंग ने तेल सप्लाई को बुरी तरह बाधित कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन रुकने से एशिया के आसपास समुद्र में रूसी तेल के टैंकर फंस गए हैं। अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि यह तेल बाजार में तुरंत लाने का तरीका है, ताकि कीमतें और न चढ़ें। उन्होंने एबीसी न्यूज से कहा, "हमें छोटे समय के लिए तेल बाजार में लाना है। लंबे समय में सप्लाई भरपूर है, चिंता की कोई बात नहीं।" ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेन्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह "ईरान के ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास" के खिलाफ स्टॉपगैप उपाय है। यह छूट सिर्फ फंसे हुए तेल पर है, नई डील्स पर नहीं, ताकि रूस को आर्थिक फायदा न हो। अमेरिका का मकसद वैश्विक कीमतों को स्थिर रखना है, क्योंकि मध्य पूर्व संकट से रिफाइनरी पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अमेरिकी नीति में नरमी है? नहीं, राइट ने साफ कहा, "यह रूस के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ तेल कीमतों को थोड़ा नीचे रखने का छोटा कदम।" इससे अमेरिका-भारत संबंधों में गहराई आती दिखती है, जहां ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। हालांकि, कुछ एनजीओ जैसे ग्लोबल विटनेस ने आलोचना की कि यह पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है। कुल मिलाकर, यह फैसला व्यावहारिक लगता है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक संकट में सैंक्शन कैसे लचीले हो जाते हैं।

भारत की नजर: रूसी तेल से ऊर्जा सुरक्षा, लेकिन निर्भरता का सवाल

भारत के लिए यह छूट किसी वरदान से कम नहीं। देश रोजाना करीब 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, जिसमें रूस से 1 मिलियन बैरल का हिस्सा पहले से है। ईरान संकट से मध्य पूर्वी सप्लाई रुकने पर रिफाइनरी बंद होने का खतरा था, लेकिन अब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और सिंगापुर के पास फंसे रूसी तेल को खरीदकर भारत अपनी जरूरत पूरी कर सकेगा। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल कूटनीति की सफलता बताया, कहते हुए कि कांग्रेस घबराहट फैला रही है। केंद्र सरकार ने कहा, "भारत को किसी देश की इजाजत की कभी जरूरत नहीं पड़ी।" फिर भी, रिफाइनरी जल्दी से 20 मिलियन बैरल के करीब तेल बुक कर रही हैं, जो घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखेगा। आर्थिक फायदे साफ हैं- सस्ता रूसी तेल खरीदकर भारत उपभोक्ताओं को राहत दे सकेगा, क्योंकि वैश्विक कीमतें ऊंची होने पर पेट्रोल-डीजल महंगे हो जाते। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का स्टॉक है, इसलिए लंबे समय तक रूस पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, "ट्रंप की इजाजत क्यों लेनी पड़ी?" यह छूट अप्रैल 4 तक है, उसके बाद क्या? अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि भारत ज्यादा अमेरिकी तेल खरीदे। भारत की ओर से स्रोतों ने बताया कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन से अपील की थी। कुल मिलाकर, यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, लेकिन यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमें विविध स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रूस-ईरान के रिश्ते को देखते हुए, भारत को सतर्क रहना होगा। यह घटना दिखाती है कि कैसे कूटनीति में लचीलापन जरूरी है, लेकिन स्वावलंबन सबसे बड़ा हथियार।

वैश्विक बाजार पर असर: कीमतें स्थिर, लेकिन आलोचना की लहर

यह छूट न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित करेगी। रूसी तेल को बाजार में लाने से सप्लाई बढ़ेगी, जो होर्मुज संकट से पैदा हुई कमी को पूरा करेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर फातिह बिरोल ने चेताया कि रूस पर गैस निर्भरता गलत होगी, लेकिन तेल के मामले में यह अस्थायी मदद साबित हो सकती है। कीमतें 90 डॉलर पर स्थिर रहेंगी, वरना और चढ़ाव आता। अमेरिका का कहना है कि इससे एशियाई रिफाइनरी पर दबाव कम होगा, और लंबे समय में अमेरिकी तेल की मांग बढ़ेगी। लेकिन आलोचना भी हो रही है। ग्लोबल विटनेस के चीफ माइक डेविस ने कहा कि यह अमेरिका का यूक्रेन को बलि चढ़ाना है ताकि तेल संकट न हो। क्रेमलिन के डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ईरान जंग से रूसी ऊर्जा की मांग बढ़ी है। ड्यूश बैंक के विश्लेषक इसे एशियाई रिफाइनरी के लिए छोटी राहत बता रहे हैं। भारत के अलावा चीन जैसे देश भी रूसी तेल पर नजर रखे हैं, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, यह कदम वैश्विक स्थिरता लाएगा, लेकिन यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सैंक्शन हमेशा नैतिक होते हैं या व्यावहारिक जरूरतें उन्हें बदल देती हैं। अगर संकट लंबा चला तो कीमतें फिर उछल सकती हैं, और विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

भविष्य की राह: अमेरिका-भारत रिश्ते में नया मोड़, लेकिन सतर्कता जरूरी

यह छूट अमेरिका-भारत संबंधों में नया अध्याय खोल सकती है। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में 25 प्रतिशत टैरिफ हटाया था, और अब यह कदम दिखाता है कि ऊर्जा सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका की शर्त साफ है- भारत को बाद में ज्यादा अमेरिकी तेल खरीदना होगा। रूस के साथ ईरान के गठजोड़ को देखते हुए, मध्य पूर्व संकट और फैल सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा मार्गों को खतरे में डालेगा। भारत को अब बायोफ्यूल और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना होगा ताकि आयात निर्भरता कम हो। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह घटना कूटनीति की ताकत दिखाती है, लेकिन लंबे समय के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। क्या यह छूट बढ़ेगी? संकेत नहीं मिले, लेकिन अगर संकट रहा तो संभव है। कुल मिलाकर, यह राहत देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है कि वैश्विक शक्तियां कैसे ऊर्जा को हथियार बनाती हैं। भारत जैसे देशों को संतुलन बनाना होगा।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

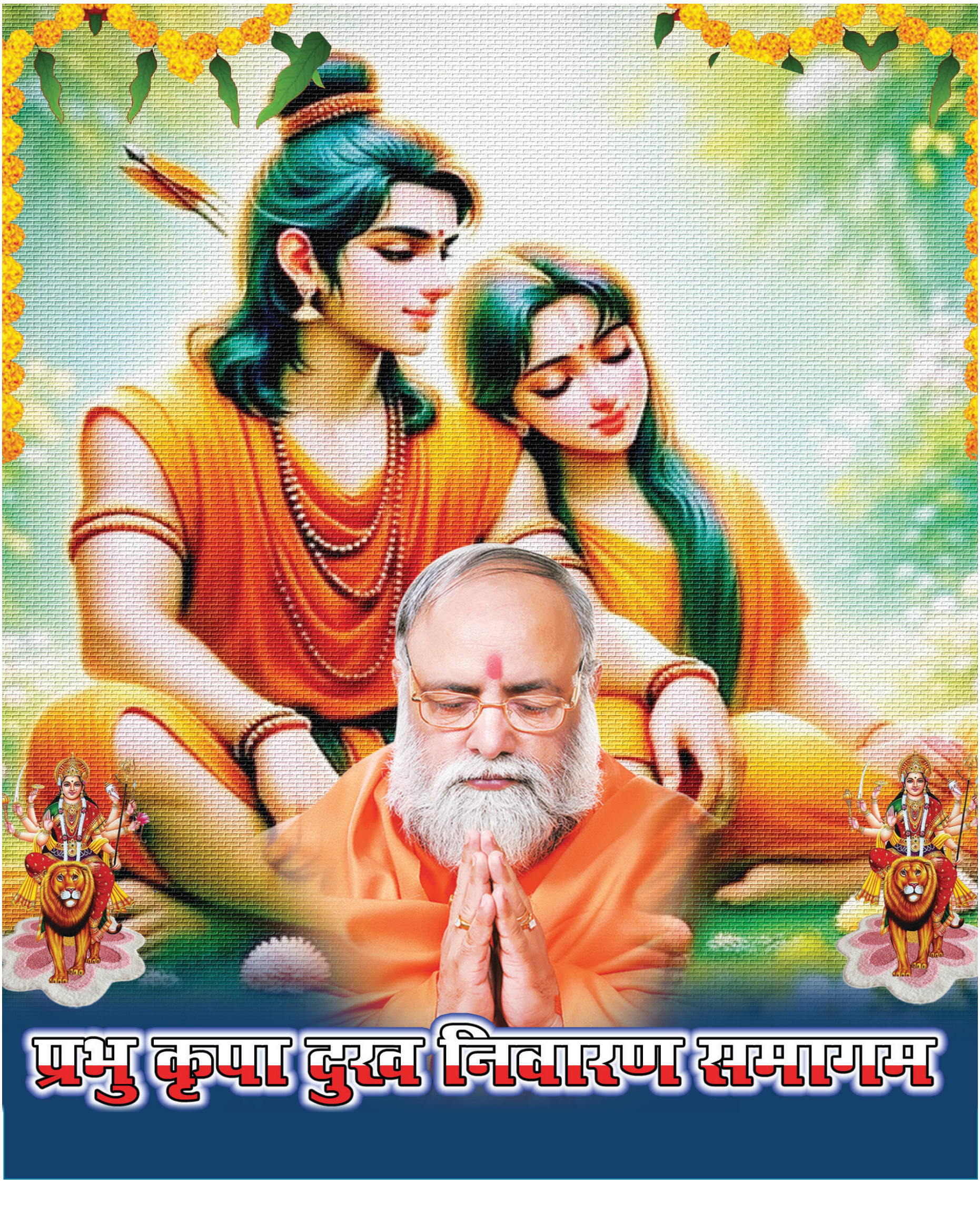

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries